भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS LINE DELHI 31 JANUARY 2026

Air passenger traffic records 3 per cent surge in first nine months of this fiscal

T E Raja Simhan
Chennai

Air passenger traffic — both domestic and international — through Indian airports rose by 3 per cent in the first nine months of this fiscal when compared with the previous year. Growth remained muted in the fiscal because of overall demand and sentiment.

Separately, international traffic between April and December 2025 increased by 7 per cent while domestic traffic saw a 2 per cent jump, according to Airports Authority of India (AAI).

Delhi retained the top spot while Chennai widened its lead over Kolkata. In April to December 2025, the airports across India handled a total of 31.18 crore passengers as against 30.36 crore in the same period previous year, according to AAI data.

Significant surge *(Domestic + International)*

Airport	Apr-Dec 2024	Apr-Dec 2025	Difference (%)
Delhi (DEL)	5,86,22,743	5,75,10,934	-1.9
Mumbai (MIAL)	4,09,87,913	4,13,07,885	0.9
Bengaluru (BIAL)	3,12,05,655	3,31,47,500	6.2
Hyderabad (GHIAL)	2,13,97,348	2,32,25,719	8.5
Chennai	1,65,76,077	1,73,48,024	4.7
Kolkata	1,61,68,148	1,56,80,550	-3.9
Total (all Indian airports)	**30,36,32,273**	**31,18,61,396**	**2.7**

Source: Airports Authority of India

TOP SPOT

Delhi (DEL) retained the top spot in this fiscal but saw a decline in passengers handled in April to December 2025. Mumbai (MIAL) was second followed by Bengaluru (BIAL) and Hyderabad (GHIAL). All three are joint venture international airports and recorded increase in passenger traffic in this period. Chennai retained the 5th position while Kolkata 6th.

While Chennai saw a 5 per cent increase in the first nine months of this fiscal, Kolkata saw a 4 per cent decline, says AAI data.

Ankit Hakhu, Director, Crisil Ratings, said the growth in airport traffic in India is likely to end at a muted 0-1 per cent on year in fiscal 2026 due to weakened demand sentiment following a major aircraft mishap and elongated monsoons in the first half of the fiscal and airline disruptions that occurred in the second half.

In fiscal 2027, however, traffic growth is anticipated to rebound to 6-7 per cent as supply-side constraints recover in the first half, resulting in a passenger volume of 430-440 million for the year, said Hakhu.

CHENNAI WIDENS GAP

In April to December 2025, the Chennai airport handled 1.73 crore passengers while Kolkata handled 1.56 crore — a difference of 16.67 lakh. In the previous year, Chennai handled 1.65 crore while Kolkata handled 1.61 crore — a difference of 4.07 lakh.

An official of a large travel agency said the Chennai airport's growth was mainly attributed to the expansion that's been going on in the last few years.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

AMAR UJALA | DELHI | 1 FEBRUARY 2026

टर्मिनल-1 तक सीधी मेट्रो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आधार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन के विस्तार के साथ ही दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन को मल्टी-लाइन इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद यात्रियों को आईजीआई एयरपोर्ट के सभी टर्मिनलों तक तेज, सीधा और आसान मेट्रो कनेक्शन मिलेगा।

गोल्डन लाइन फिलहाल तुगलकाबाद से दिल्ली एरोसिटी तक बनाई जा रही है, जिसका 80 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है। अब इस कॉरिडोर को एक ओर कालिंदी कुंज तक एलिवेटेड रूप में बढ़ाया जाएगा, जबकि दूसरी ओर एरोसिटी से आगे आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 तक विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसके बाद कालिंदी कुंज, तुगलकाबाद और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों से टर्मिनल-1 तक बिना लाइन बदले मेट्रो से पहुंचना संभव हो सकेगा। इस विस्तार से यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मौजूदा जटिल रूट्स से छुटकारा मिलेगा। अभी दक्षिणी दिल्ली या नोएडा से टर्मिनल-1 पहुंचने के लिए यात्रियों को ब्लू, वॉयलेट या मैजेंटा लाइन के बीच कई बार मेट्रो बदलनी पड़ती है। कुछ रूट्स पर यात्रियों को स्टेशन बदलने के लिए पैदल चलना भी पड़ता है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते हैं। गोल्डन लाइन के विस्तार के बाद यह सफर कहीं ज्यादा सीधा और समय बचाने वाला हो जाएगा।

इंटरचेंज स्टेशन 290 मीटर लंबा होगा... : गोल्डन लाइन के तहत एरोसिटी पर बनने वाला नया इंटरचेंज स्टेशन करीब 290 मीटर लंबा होगा, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में अब तक का सबसे लंबा स्टेशन होगा। सामान्य इंटरचेंज स्टेशन की तुलना में यह कहीं अधिक बड़ा होगा, ताकि बढ़ती यात्री संख्या और एयरपोर्ट ट्रैफिक को आसानी से संभाला जा सके। डीएमआरसी अधिकारियों के अनुसार, इस मल्टी-लाइन कनेक्टिविटी से न सिर्फ एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा, बल्कि दक्षिणी दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद से आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों का सफर भी तेज और सुगम होगा।

मेट्रो का चल रहा निर्माण कार्य। अमर उजाला

प्लेटफॉर्म-टू-प्लेटफॉर्म मिलेगी कनेक्टिविटी

- एरोसिटी स्टेशन पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, गोल्डन लाइन और मैजेंटा लाइन का आपसी जुड़ाव यात्रियों के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। यहां प्लेटफॉर्म-टू-प्लेटफॉर्म और कन्कोर्स-टू-कन्कोर्स कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे बिना स्टेशन से बाहर निकले लाइन बदलना संभव होगा। यही नहीं, भविष्य में यहां एनसीआरटीसी के दिल्ली–अलवर कॉरिडोर को जोड़ने की भी तैयारी है, जिससे यह स्टेशन ट्रिपल इंटरचेंज हब बन सकता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

AMAR UJALA DELHI 1 FEBRUARY 2026

पीएम मोदी संत रविदास जयंती पर आज डेरा सचखंड बल्लां में नवाएंगे शीश

आदमपुर हवाईअड्डे को संत रविदास का नाम देंगे, हलवारा के टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को संत रविदार की 646वीं जयंती पर पंजाब के जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां जाएंगे और कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वह आदमपुर हवाई अड्डे का नाम संत रविदास के नाम पर रखेंगे। इसके अलावा हलवारा हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे।

पीएम ने कहा, संत गुरु रविदास की जयंती के शुभ अवसर पर आदमपुर हवाईअड्डे का नामकरण पूजनीय संत और समाज सुधारक को श्रद्धांजलि है। जिनकी समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती रहती हैं। पंजाब में विमानन अवसंरचना को और आगे बढ़ाते हुए हलवारा हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भी जनता को समर्पित करेंगे। टर्मिनल भवन राज्य के लिए एक नया प्रवेश द्वार स्थापित करेगा, जो लुधियाना और उसके आसपास के औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लुधियाना में पहले हवाई अड्डे का रनवे अपेक्षाकृत छोटा था, जो छोटे आकार के विमानों के लिए उपयुक्त था। कनेक्टिविटी में सुधार और बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए, नया सिविल एन्क्लेव विकसित किया गया है। ब्यूरो

डेरा बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास से मुलाकात की 2019 की यह तस्वीर पीएम मोदी ने पोस्ट की है।

टर्मिनल में कई हरित व ऊर्जा दक्ष सुविधाएं शामिल

पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री के सतत और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप, टर्मिनल में कई हरित और ऊर्जा-दक्ष सुविधाएं शामिल हैं। इनमें एलईडी प्रकाश व्यवस्था, इन्सुलेटेड छत, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज और जल शोधन संयंत्र तथा भूदृश्य निर्माण के लिए पुनर्चक्रित जल का उपयोग शामिल है.इसका स्थापत्य डिजाइन पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो यात्रियों को एक विशिष्ट और क्षेत्रीय रूप से प्रेरित यात्रा अनुभव प्रदान करती है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

AMAR UJALA DELHI 1 FEBRUARY 2026

विस्तार **एरोसिटी स्टेशन पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, गोल्डन लाइन और मैजेंटा लाइन की मिलेगी सुविधा**

टर्मिनल-1 तक सीधी मेट्रो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को नया आधार

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन के विस्तार के साथ ही दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन को मल्टी-लाइन इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद यात्रियों को आईजीआई एयरपोर्ट के सभी टर्मिनलों तक तेज, सीधा और आसान मेट्रो कनेक्शन मिलेगा। गोल्डन लाइन फिलहाल तुगलकाबाद से दिल्ली एरोसिटी तक बनाई जा रही है, जिसका 80 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है।

अब इस कॉरिडोर को एक ओर कालिंदी कुंज तक एलिवेटेड रूप में बढ़ाया जाएगा, जबकि दूसरी ओर एरोसिटी से आगे आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 तक विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसके बाद कालिंदी कुंज, तुगलकाबाद और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों से टर्मिनल-1 तक बिना लाइन बदले मेट्रो से पहुंचना संभव हो सकेगा। इस विस्तार से यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मौजूदा जटिल रूट्स से छुटकारा मिलेगा। अभी दक्षिणी दिल्ली या नोएडा से टर्मिनल-1 पहुंचने के लिए यात्रियों को ब्लू, वॉयलेट या मैजेंटा लाइन के बीच कई बार मेट्रो बदलनी पड़ती है। कुछ रूट्स पर यात्रियों को स्टेशन बदलने के लिए पैदल चलना भी पड़ता है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते हैं। गोल्डन लाइन के विस्तार के बाद यह सफर कहीं ज्यादा सीधा और समय बचाने वाला हो जाएगा।

मेट्रो का निर्माण कार्य।

प्लेटफॉर्म-टू-प्लेटफॉर्म मिलेगी कनेक्टिविटी

एरोसिटी स्टेशन पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, गोल्डन लाइन और मैजेंटा लाइन का आपसी जुड़ाव यात्रियों के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। यहां प्लेटफॉर्म-टू-प्लेटफॉर्म और कन्कोर्स-टू-कन्कोर्स कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे बिना स्टेशन से बाहर निकले लाइन बदलना संभव होगा। यही नहीं, भविष्य में यहां एनसीआरटीसी के दिल्ली-अलवर कॉरिडोर को जोड़ने की भी तैयारी है, जिससे यह स्टेशन ट्रिपल इंटरचेंज हब बन सकता है।

इंटरचेंज स्टेशन 290 मीटर लंबा होगा

इस परियोजना की एक और खास बात यह है कि गोल्डन लाइन के तहत एरोसिटी पर बनने वाला नया इंटरचेंज स्टेशन करीब 290 मीटर लंबा होगा, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में अब तक का सबसे लंबा स्टेशन होगा। सामान्य इंटरचेंज स्टेशन की तुलना में यह कहीं अधिक बड़ा होगा, ताकि बढ़ती यात्री संख्या और एयरपोर्ट ट्रैफिक को आसानी से संभाला जा सके। डीएमआरसी अधिकारियों के अनुसार, इस मल्टी-लाइन कनेक्टिविटी से न सिर्फ एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा, बल्कि दक्षिणी दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद से आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों का सफर भी तेज और सुगम होगा। मेट्रो के जरिए एयरपोर्ट पहुंचना अब निजी वाहनों और टैक्सियों पर निर्भर नहीं रहेगा, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम होने की उम्मीद है।

BUSINESS LINE | DELHI | 31 JANUARY 2026

India will need 400 airports, 3,000 commercial aircraft by 2047: Report

Our Bureau
Hyderabad

A super-connected India will require an integrated grid of 400 airports, supported by a commercial fleet of about 3,000 aircraft, by 2047, according to a KPMG-FICCI report.

The report, 'Paving the future of aviation in Viksit Bharat @ 2047', released at the ongoing Wings India 2026 here, states that the country is the world's third-largest domestic aviation market and on track to becoming the third-largest globally, enabled by rapid fleet induction and record aircraft orders.

India currently operates 164 airports, with a long-term plan for a balanced network of mega hubs, national gateways and cost-efficient regional airports.

Air cargo throughput stands at about 3.7 million tonnes annually, with nearly 80 per cent routed through the five largest airports. The report calls for fully digitised, multimodal cargo ecosystems to drive competitiveness. The maintenance, repair and overhaul (MRO) market is set to grow from $2.5 billion to $7 billion by 2035.

SAF DREAMS

"India has the potential to build a globally competitive sustainable aviation fuel (SAF) industry, leveraging its diverse feedstocks, substantial refining capacity, bioenergy experience and strong policy momentum," the report said.

The National Aviation Skilling Mission will be essential to meet the projected workforce requirement of 40,000 pilots and 38,000 aircraft maintenance engineers by 2047. India's civil aviation sector is undergoing a structural shift — from a facilitator of mobility to a strategic engine of economic growth, employment and competitiveness. "The next two decades offer an unprecedented opportunity to build a future-ready aviation economy, supported by a unified national aviation technology stack, next-generation hub airports, and a deep domestic industrial base across manufacturing, maintenance, talent and finance," the report added.

"With AI-powered operations, multimodal integration, and future-ready infrastructure, the opportunity to support over a billion annual passenger journeys by 2047 is within reach," Akhilesh Tuteja, Partner and Head-Clients and Markets, KPMG in India, said.

Strengthening domestic manufacturing, MRO, leasing, cargo handling and skilling will be essential to building lasting strategic advantage, he added.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DESHBANDHU | DELHI | 1 FEBRUARY 2026

टर्मिनल-1 तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का सबसे बड़ा इंटरचेंज हब बनेगा एयरोसिटी

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन को इस लाइन के सबसे बड़े इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस स्टेशन का विस्तार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) फेज-4 के अंतर्गत निर्माणाधीन तुगलकाबाद-एयरोसिटी गोल्डन लाइन कॉरिडोर से अतिरिक्त कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में इस कॉरिडोर के एयरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 स्टेशन तक के 2.263 किलोमीटर तक के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई है।

डीएमआरसी के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) अनुज दयाल ने बताया कि भविष्य में इस स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज के रूप में विकसित किया जाएगा। मैजेंटा लाइन के आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 स्टेशन तक गोल्डन लाइन के विस्तार को स्वीकृति मिलने के बाद दक्षिण दिल्ली के कई क्षेत्रों से यात्रा करने वाले यात्रियों को टर्मिनल-1 तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

एनसीआरटीसी के प्रस्तावित अलवर कॉरिडोर के लिए दिल्ली एयरोसिटी पर इंटरचेंज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नए दिल्ली एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और गोल्डन लाइन के बीच प्लेटफॉर्म-टू-प्लेटफॉर्म एवं कंकोर्स-टू-कंकोर्स पेड एरिया कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। यह प्लेटफॉर्म लगभग 22 मीटर की गहराई पर निर्मित किया जाएगा। गोल्डन लाइन का नया स्टेशन लगभग 290 मीटर लंबा होगा, ताकि इंटरचेंज की सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

अनुज दयाल ने बताया कि इंटरचेंज स्टेशन की लंबाई लगभग 260 मीटर होती है। योजना के अनुसार, गोल्डन लाइन और प्रस्तावित एनसीआरटीसी कॉरिडोर एक-दूसरे को लगभग तिरछी दिशा में क्रॉस करेंगे। भविष्य में एनसीआरटीसी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए आवश्यक संरचनात्मक प्रावधान पहले से ही स्टेशन में शामिल किए जाएंगे। यह नई इंटरचेंज सुविधा दक्षिण दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित करेगी, जिन्हें एयरोसिटी-तुगलकाबाद मेट्रो कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। तुगलकाबाद, आंबेडकर नगर, खानपुर आदि क्षेत्रों के यात्री अब आईजीआई हवाईअड्डे के सभी टर्मिनलों तक शीघ्र और सहज रूप से पहुंच सकेंगे।

आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ तक कॉरिडोर

डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ तक फेज-5 ए कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिसके कारण ही लाइन का रंग बदला गया है। इस नए रूट पर 9 स्टेशन होंगे। इसमें आरके आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल-हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल होंगे। इस कॉरीडोर के शुरू होने से राजीव चौक पर भीड़ कम होगी। एयरपोर्ट लाइन और राजीव चौक ब्लू लाइन के बीच एक डेडिकेटेड सबवे बनाने का प्रस्ताव है। इससे यात्री सीधे एयरपोर्ट लाइन से राजीव चौक पहुंच सकेंगे, जिससे कनॉट प्लेस स्टेशन पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DESHBANDHU DELHI 1 FEBRUARY 2026

भास्कर एक्सक्लूसिव अधिगृहीत जमीन के मालिकों को मिलेंगे प्लॉट

एयरपोर्ट के पास मोहाली में बनेगा मेगा बिजनेस हब, एक्सपो सिटी कमर्शियल जोन घोषित

सुखबीर सिंह बाजवा | चंडीगढ़

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक जल्द ही एक नया मेगा बिजनेस हब विकसित किया जाएगा। इसके लिए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने एक्सपो सिटी के लिए 183.5 एकड़ भूमि को आधिकारिक रूप से कमर्शियल जोन घोषित कर दिया है। यह भूमि एयरपोर्ट के बेहद करीब स्थित है। गमाडा के इस फैसले के बाद एक्सपो सिटी को सेक्टर-87 के बाद मोहाली का दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल हब माना जा रहा है।

गमाडा के अनुसार, एक्सपो सिटी का चयन इसकी मजबूत लोकेशन स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर किया गया है। यह क्षेत्र चंडीगढ़ शहर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ट्राइसिटी के प्रमुख ट्रैफिक कॉरिडोर से सीधे जुड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट में सफीपुर, लाडयाली, रुड़का और धर्मगढ़ जैसे गांवों की भूमि ली गई है। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर और प्रदर्शनी हॉल बनाए जाएंगे, जहां बड़े पैमाने पर व्यापारिक कार्यक्रम, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकेंगी। इसमें एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर लगभग 10 एकड़ का होगा। यहां 4 से 5 होटल की साइट की नीलामी होगी। अधिसूचना के तहत एक्सपो जोन में आने वाले भूमि मालिकों को प्रति एकड़ 800 वर्ग गज के कमर्शियल प्लॉट दिए जाएंगे। यह प्रावधान केवल एक्सपो सिटी क्षेत्र तक सीमित रहेगा। गमाडा अधिकारियों का कहना है कि इससे भूमि मालिकों को सीधे व्यावसायिक लाभ मिलेगा। साथ ही, निजी निवेशकों और बड़े डेवलपर्स की रुचि भी इस क्षेत्र में बढ़ने की संभावना है।

इस प्रोजेक्ट में चार गांवों की जमीन शामिल

एलांते मॉल से चार गुना बड़ा मॉल बनाया जाएगा

गमाडा की मास्टर प्लानिंग के तहत एक्सपो सिटी को एक बहुआयामी कमर्शियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना के अनुसार, 10 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक आधुनिक एग्जिबिशन ग्राउंड बनाया जाएगा, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले, औद्योगिक प्रदर्शनियां, कॉर्पोरेट इवेंट्स और बड़े सम्मेलन आयोजित किए जा सकेंगे। इसके अलावा, 20 एकड़ क्षेत्र में एक विशाल मेगा मॉल प्रस्तावित है, जो आकार और क्षमता में चंडीगढ़ के एलांते मॉल से लगभग चार गुना बड़ा होगा। इस मॉल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एंटरटेनमेंट जोन, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं होंगी, जिससे यह इलाका 24×7 एक्टिव कमर्शियल जोन बन सकेगा।

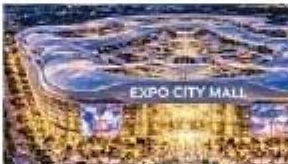

ऐसा होगा मॉल

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DESHBANDHU DELHI 1 FEBRUARY 2026

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर दिल्ली एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन एक बड़ा इंटरचेंज हब बनेगा

नई दिल्ली, 31 जनवरी (देशबन्धु)। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर स्थित दिल्ली एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के एक प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। इस स्टेशन का विस्तार फेज़ चार के अंतर्गत निर्माणाधीन तुगलकाबाद-एयरोसिटी गोल्डन लाइन कॉरिडोर से अतिरिक्त कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। यह जानकारी अनुज दयाल प्रधान अधिशासी निदेशक, कॉर्पोरेट संचार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दी।

हाल ही में इस कॉरिडोर के एयरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 स्टेशन 2.263 किलोमीटर तक विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। भविष्य में इस स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि एनसीआरटीसी के प्रस्तावित अलवर कॉरिडोर के लिए दिल्ली एयरोसिटी पर इंटरचेंज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नए दिल्ली एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और गोल्डन लाइन के बीच प्लेटफॉर्म-टू-प्लेटफॉर्म एवं

- भविष्य में स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज के रूप में विकसित किया जाएगा
- गोल्डन लाइन का नया स्टेशन लगभग 290 मीटर लंबा होगा

कंकोर्स-टू-कंकोर्स पेड एरिया कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। यह प्लेटफॉर्म लगभग 22 मीटर की गहराई पर निर्मित किया जाएगा। गोल्डन लाइन का नया स्टेशन लगभग 290 मीटर लंबा होगा, ताकि इंटरचेंज की सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। सामान्यत: इंटरचेंज स्टेशन की लंबाई लगभग 260 मीटर होती है। योजना के अनुसार, गोल्डन लाइन और प्रस्तावित एनसीआरटीसी कॉरिडोर एक-दूसरे को लगभग तिरछी दिशा में क्रॉस करेंगे। भविष्य में एनसीआरटीसी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए आवश्यक संरचनात्मक प्रावधान पहले से ही स्टेशन में शामिल किए जाएंगे।

यह नई इंटरचेंज सुविधा दक्षिण दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित करेगी, जिन्हें एयरोसिटी-तुगलकाबाद मेट्रो कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर, खानपुर आदि क्षेत्रों के यात्री अब इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभी टर्मिनलों तक शीघ्र और सहज रूप से पहुंच सकेंगे। मैजेंटा लाइन के आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 स्टेशन तक गोल्डन लाइन के विस्तार को स्वीकृति मिलने के पश्चात, दक्षिण दिल्ली के कई क्षेत्रों से यात्रा करने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DESHBANDHU DELHI 1 FEBRUARY 2026

एयरपोर्ट प्रभावित समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने की पंचायत

जेवर, 31 जनवरी (देशबन्धु)। निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण व विस्थापन से प्रभावित गांव रामनेर में ग्रामीणों ने समस्याओं को लेकर शनिवार को शिव मंदिर परिसर में पंचायत का आयोजन किया। जिसमें विस्थापन से जुड़ी समस्याओं व अन्य मांगों पर विचार विमर्श किया गया। मांगों का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने विस्थापित नही होने की चेतावनी दी। ग्रामीणों द्वारा लेखपाल पर भी गंभीर आरोप लगाए गए।

शैलेश ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत बारह साला (भार मुद्रित प्रमाण पत्र) व अन्य कागजातों को लेखपाल द्वारा फर्जी अपूर्ण बताकर बेवजह परेशान किया जा रहा है। जबकि सहमति लेते वक्त अधिकारियों द्वारा गांव-गांव कैंप लगाकर किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि अधिग्रहण से प्रभावित प्रत्येक गांव में कैंप लगाए जाए जिनमें ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण किया जा सके तथा किसान तहसील में चक्कर काटने को विवश न हो। विस्थापन स्थल पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए व प्रभावित परिवार के एक सदस्य को स्थाई रोजगार उपलब्ध कराने आदि मांगों को पूरा करने की मांग की। इस मौके पर प्रवीण कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विजयपाल, कमल शर्मा, हरपाल सिंह, वीरेंद्र पाल, कुंवरपाल, नानक ठाकुर, केके शर्मा, ईश्वरचंद शर्मा, संजय, योगेश ठाकुर आदि सेंकड़ों लोग मौजूद रहे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

HINDUSTAN DELHI 1 FEBRUARY 2026

कोहरा फिर बढ़ने से नांदेड़ की उड़ान रद्द

ट्रांस हिंडन। कोहरा बढ़ने से शनिवार को नांदेड़ की उड़ान रद्द रही। साढ़े चार डिग्री तक अधिकतम पारा गिरने से दिन में धूप निकलने के बाद भी सर्दी अधिक महसूस हुई। हिंडन एयरपोर्ट निदेशक डॉ. चिलका महेश ने बताया कि यात्रियों को परेशानी नही हुई क्योंकि सूचना पहले ही दे दी गई थी।

नई दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अरब लीग के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर दोनों पक्षों ने चर्चा की। • प्रेट्र

प्रधानमंत्री आज हलवारा हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पंजाब दौरे पर रहेंगे। मोदी हलवारा हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और आदमपुर हवाई अड्डे का नाम संत रविदास के नाम पर रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री डेरा सचखंड बल्लां भी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रधानमंत्री रविवार को जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डा जाएंगे और इसके नए नाम 'श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट' का अनावरण करेंगे।

Modi to visit Punjab today to unveil renamed airport

The Hindu Bureau
CHANDIGARH

Narendra Modi

Prime Minister Narendra Modi will visit Punjab on Sunday, during which he will unveil the renaming of Adampur airport in Jalandhar district as 'Sri Guru Ravidas Ji' Airport. The Prime Minister will also inaugurate the terminal building at Halwara Airport in Ludhiana.

To celebrate the 649th birth anniversary of Guru Ravidas, the renaming of Adampur airport honours the revered saint and social reformer..., an official statement said.

Mr. Modi will be at Dera Sach Khand Ballan at Ballan village and will meet Sant Niranjan Dass, who was recently named for the Padma Shri. The visit assumes political significance, pointing to the party's Dalit outreach in the run-up to the Punjab Assembly election due in early 2027.

The statement added that the terminal building at Halwara Airport will serve as a new gateway for Punjab, connecting Ludhiana and its surrounding industrial and agricultural belt, thereby strengthening the State's aviation infrastructure. Halwara also houses an Indian Air Force station.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

NAVODAYA TIMES DELHI 1 FEBRUARY 2026

पीएम मोदी आज पंजाब में, हलवारा हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन

आदमपुर हवाई अड्डे का नाम संत रविदास के नाम पर रखेंगे

नई दिल्ली, 31 जनवरी (एजैंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पंजाब में हलवारा हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और आदमपुर हवाई अड्डे का नाम संत रविदास के नाम पर रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया, 'संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के शुभ अवसर पर आदमपुर हवाई अड्डे का नामकरण इस पूजनीय संत और समाज सुधारक को श्रद्धांजलि है, जिनकी समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं भारत के सामाजिक मूल्यों (शेष पृष्ठ 11 कालम 1 पर)

कनेक्टिविटी में होगा सुधार

लुधियाना जिले में स्थित हलवारा में भारतीय वायुसेना का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेशन भी है। लुधियाना में पहले हवाई अड्डे का रनवे अपेक्षाकृत छोटा था, जो छोटे आकार के विमानों के लिए उपयुक्त था। कनेक्टिविटी में सुधार और बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए, हलवारा में एक नया 'सिविल एन्क्लेव' विकसित किया गया है, जिसका रनवे लंबा है और ए320 जैसे विमानों की आवाजाही के लिए सक्षम है।

डेरा बल्लां, पांच विद्यालयों में बम विस्फोट की धमकी

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां के मुख्यालय का दौरा करने से एक दिन पहले शनिवार को संप्रदाय और पांच विद्यालयों को बम विस्फोट की धमकियां मिलीं। अधिकारियों ने बताया कि गुरु रविदास जयंती से संबंधित अवकाश के कारण बंद स्कूलों में व्यापक सुरक्षा जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के कारण डेरा परिसर पहले से ही कड़ी सुरक्षा में है। अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों को ईमेल भेजे गये थे, जिनमें इन्हें और डेरा बल्लां को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उन्होंने बताया कि संदेशों में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी 'खालिस्तानियों के दुश्मन' हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

PIONEER DELHI 1 FEBRUARY 2026

Aerocity metro station to become key interchange hub

PIONEER NEWS SERVICE
■ New Delhi

The Delhi Aerocity metro station on the Airport Express Line is set to become a major interchange hub of the city's metro network following its planned integration with the Tughlakabad-Aerocity Golden Line corridor. The station is being developed to provide seamless connectivity to the Tughlakabad-Aerocity Golden Line corridor, which is currently under construction as part of Phase 4.

An approval has recently been granted for extending the Golden Line corridor from Aerocity to the Terminal 1 Indira Gandhi International (IGI) Airport station, covering a stretch of about 2.26 km. The move aims to improve airport connectivity for commuters from south Delhi, according to the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC).

According to the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), the expanded station will not only serve as a key interchange between the Airport Express Line and the Silver (Golden) Line but will also have future provisions to become a triple interchange hub.

The National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) has proposed an interchange facility at Delhi Aerocity for its planned corridor connecting Delhi to Alwar, further enhancing the station's strategic importance. According to the DMRC, the new Aerocity interchange will feature platform-to-platform connectivity on one side and concourse-to-concourse paid area connectivity between the Airport Express Line and the Golden Line, with the platforms expected to be located at a depth of around 22 metres.

It said the Golden Line station at Aerocity will be significantly longer — about 290 metres — to accommodate interchange requirements, compared to the usual interchange station length of around 260 metres.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

PIONEER DELHI 1 FEBRUARY 2026

PM Modi to inaugurate civil terminal of Halwara airport

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi

Prime Minister Narendra Modi will on Sunday inaugurate the civil terminal of the Halwara airport in Punjab and name the Adampur airport after Sant Ravidas.

"On the auspicious occasion of the 649th birth anniversary of Sant Guru Ravidas ji, the renaming of Adampur Airport honours the revered saint and social reformer whose teachings of equality, compassion, and human dignity continue to inspire India's social ethos," a statement from the PMO said.

The prime minister will visit Adampur airport on Sunday where he will unveil its new name — Sri Guru Ravidas Ji Airport.

Further advancing aviation infrastructure in Punjab, the terminal building at Halwara airport will establish a new gateway for the state, catering to Ludhiana and its surrounding industrial and agricultural hinterland.

Located in Ludhiana district, Halwara is also home to a strategically important Indian Air Force station.

The previous airport at Ludhiana had a relatively small runway, suitable for small-size aircrafts.

To improve connectivity and accommodate larger aircrafts, a new civil enclave has been developed at Halwara which has a longer runway capable of handling A320-type aircrafts.

"Aligned with prime minister's vision of sustainable and environmentally responsible development, the terminal incorporates several green and energy-efficient features, including LED lighting, insulated roofing, rainwater harvesting systems, sewage and water treatment plants, and the use of recycled water for landscaping," the PMO statement said.

The architectural design reflects Punjab's rich cultural heritage, offering passengers a distinctive and regionally inspired travel experience, the statement said.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

STATESMEN | DELHI | 1 FEBRUARY 2026

Delhi's Aerocity Metro Station to become major interchange hub

STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 31 January

The Delhi Aerocity Metro station on the Airport Express Line is all set to become a major interchange hub of the Delhi Metro network as it is being expanded to provide additional connectivity to the Tughlakabad – Aerocity Golden Line corridor, being constructed as part of Phase 4.

"Recently, approval has also been received for the extension of this corridor from Aerocity to Terminal 1 IGI Airport station (2.263 kms)," a DMRC spokesperson said on Saturday.

In the future, the station will also have the provision of being turned into a triple interchange, as the National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) will have interchange facilities at Delhi Aerocity for its proposed corridor to Alwar. The new Delhi Aerocity Metro station will have platform-to-platform (for one side) as well as concourse-to-concourse paid area connectivity between the Airport Express Line and the Golden Line. The platform will come up at a depth of approximately 22 metres.

The new station for the Golden Line will be significantly longer, at approximately 290 metres, to accommodate the interchange requirements. Generally, the length of an interchange station is about 260 metres.

As per the alignment planned, the Golden Line and the proposed NCRTC corridor will cross each other almost diagonally.

The necessary structural provisions for the construction of the NCRTC platform shall be kept in the station for its future integration.

This new interchange facility will be a major connectivity boost for various areas of South Delhi, which will be connected by the Aerocity – Tughlakabad Metro corridor. Areas such as Tughlakabad, Ambedkar Nagar, Khanpur, etc., will have quick access to all terminals of the Indira Gandhi International Airport.

Now, with the approval of the extension of the Golden Line till Terminal 1 IGI Airport station of Magenta Line, passengers traveling from many south Delhi areas will have direct access to Terminal 1 of the airport.

Passengers from Terminal 1D will also be able to take the Airport Line from Aerocity through Metro by taking the Golden Line from Terminal 1 IGI Airport to Aerocity.

TIMES OF INDIA DELHI 1 FEBRUARY 2026

PM to rename Adampur airport after Ravidas in Dalit outreach

Kumar.Rakesh
@timesofindia.com

New Delhi: PM Narendra Modi will on Sunday rename the Adampur airport after the saint Ravidas, a revered figure especially among Dalits, and visit Dera Sachkhand Ballan, the headquarters of the Ravidassia community, as part of continuing outreach to his followers present in big numbers not only in Punjab but in several other states.

Modi's decision to time the renaming of the facility as "Sri Guru Ravidas Ji Airport" — demand for which was being made for a long time — with the saint's 649th birth anniversary and associating himself with the event and scheduling a visit to the dera underlines his emphasis on cultivating a community which is important to BJP in terms of not only its politics but also its larger cultural agenda.

Assembly polls are due in Punjab in the first quarter of next year

He has in the past years launched projects for the development of the birthplace of Ravidas, a Bhakti movement poet-saint born in Varanasi, which is Modi's parliamentary constituency, for building his memorial in Sagar in MP and visited Ravidas temples to pay tributes.

During his visit, Modi will attend a public programme and interact with Niranjan Dass, the dera's spiritual head, who was awarded a Padma Shri this Republic Day eve.

The dera is based in Jalandhar, a part of Doaba region where the concentration of SCs is higher than the rest of the state. While Dalits account for nearly 32% of the population in Punjab, more than any other state, they are nearly 42% in Doaba.

Though Dalits in Punjab are divided in several subgroups, Raviadassia community, which comprises 10-12% of the population, is one of the bigger ones and Ravidas is a respected figure among SCs. Reaching out to disadvantaged castes has been a part of BJP's drive, for its agenda of Hindu cohesion and has helped the party's growth. Punjab assembly elections are due in the first quarter of next year.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

TRIBUNE DELHI 1 FEBRUARY 2026

PM to visit Dera Ballan today; 8K cops deployed amid threat email

Will attend event to mark Guru Ravidas birth anniv

Tribune News Service

NEW DELHI/JALANDHAR, JAN 31

As Prime Minister Narendra Modi arrives at Dera Sachkhand Ballan in Jalandhar district on Sunday — his first visit to Punjab since September last year — to mark the 649th birth anniversary of Guru Ravidas, massive security arrangements have been put in place, with the deployment of about 8,000 police personnel from 26 districts at the venue.

The PM will also unveil a plaque for renaming of the Adampur airport after Guru Ravidas and inaugurate the new terminal of Halwara airport through videoconferencing.

Ahead of the high-profile visit, a threatening email was received by four private schools in the city on Saturday morning. The emails did not mention any threat to schools but targeted the PM. One email stated, "Full respect for Guru Ravidas ji but Modi is our enemy. We have no issues with Sant Niranjan Dass (head of Dera Ballan)."

The email hinted at avenging the killing of Hardeep Nijjar in Canada in June 2023. All schools in Jalandhar were closed on Saturday due to the shobha yatra of Guru Ravidas. This will be Modi's third visit to Punjab since January 5, 2022, which was cut short due to a major security breach. The PM's convoy was stranded on a flyover in Ferozepur for nearly 20 minutes due to a protest on the road, forcing him to return to Bathinda airport without attending the scheduled rally.

He later visited the Adampur Air Base in May 2025 after Operation Sindoor and Gurdaspur in September for a survey of flood-affected areas. Meanwhile, a helipad for the landing of PM's copter has been readied within the dera. Security drills have been conducted in coordination with IAF teams and the Special Protection Group. A waterproof tent has been set up for a gathering of around 1,500 devotees (mostly invited after due security clearances). Earlier, the PM will land at the Adampur Air Force Base

CONTINUED ON PAGE 6

A picture tweeted by PM of his interaction with Sant Niranjan Dass in 2019.

TO RENAME ADAMPUR AIRPORT

PM Modi will visit the Adampur base where he will unveil the plaque for renaming of the Adampur airport as Sri Guru Ravidas Ji Airport and inaugurate the new terminal of Halwara airport via videoconferencing.

PM to visit Dera Ballan today; 8,000 cops...

around 3.45 pm, about 13 km from the dera. At the IAF base, he will unveil the plaque for renaming of the Adampur airport as Sri Guru Ravidas Ji Airport and inaugurate the new terminal of Halwara airport via video conferencing.

He will then fly from Adampur to the dera in an all-weather MI-17 helicopter. With a storm predicted on Sunday evening, a drill to bring him to the venue by road in a cavalcade was also conducted.

In an official statement on Saturday, the PMO said, "The PM will participate in a public programme in the honour of Guru Ravidas. At 4.30 pm, he will visit the temple, where he will offer floral tributes to the portrait of Guru Ravidas and the statue of Sant Sarwan Dass, the second Gaddi-Nashin of Dera Sachkhand Ballan. Thereafter, he will perform ardas and undertake parikrama. Around 4.45 pm, the PM will arrive on the dais and at 5 pm, he will address the gathering."

"On the occasion of the 649th birth anniversary of Guru Ravidas, the renaming of Adampur airport honours the revered saint and social reformer whose teachings of equality, compassion and human dignity continue to inspire India's social ethos," the statement said.

Officials said further advancing aviation infrastructure in Punjab, the terminal building at Halwara Airport would establish a new gateway for the state, catering to Ludhiana and its surrounding industrial and agricultural hinterland. Located in Ludhiana district, Halwara is also home to a strategically important IAF station.

"The earlier airport at Ludhiana had a relatively small runway, suitable for small aircraft. To improve connectivity and accommodate larger aircraft, a new civil enclave has been developed at Halwara with a longer runway capable of handling A320-type aircraft," the PMO said.

Aligned with the PM's vision of sustainable and environmentally responsible development, the terminal incorporates several green and energy-efficient features. The architectural design reflects Punjab's rich cultural heritage.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate
TRIBUNE DELHI 1 FEBRUARY 2026

Delhi Aerocity Metro station to be developed as key interchange hub

EXPANSION PHASE-4

ANSHITA MEHRA
TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, JANUARY 31

The Delhi Aerocity Metro station on the Airport Express Line is set to be developed as a major interchange hub of the Delhi Metro network, with enhanced connectivity under Phase-4 of the Metro expansion project, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) said on Saturday.

The station is being expanded to integrate with the upcoming Tughlakabad-Aerocity Golden Line corridor. Recently, the government approved a 2.263-km extension of this corridor from Aerocity to Terminal 1 of Indira Gandhi International (IGI) Airport.

DMRC officials said, in future, Delhi Aerocity could become a triple interchange station, as the National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) plans to provide interchange facilities here for its proposed corridor to Alwar.

The Aerocity Golden Line corridor, being constructed as part of Phase-4 of the Metro expansion project.

Necessary structural provisions are being incorporated in the design to enable seamless future integration.

The new Aerocity station will offer platform-to-platform connectivity on one side, along with concourse-to-concourse paid-area access between the Airport Express Line and the Golden Line.

The new platform will be constructed at a depth of around 22 m.

The Golden Line station at Aerocity will be approximately 290-m, longer than the usual 260-m length of most interchange stations, to accommodate passenger movement and interchange requirements. The Golden Line and the proposed NCRTC corridor will intersect diagonally, according to the alignment plan.

Officials said the project would significantly improve Metro connectivity for several south Delhi localities, including Tughlakabad, Ambedkar Nagar and Khanpur, by providing faster access to all IGI Airport terminals. With the extension of the Golden Line to Terminal 1 (Magenta Line station), passengers from south Delhi will get direct Metro access to Terminal 1.

Travellers from Terminal 1D will also be able to access the Airport Express Line by taking the Golden Line to Aerocity and then switching lines.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

AMAR UJALA | DELHI | 1 FEBRUARY 2026

एविएशन को मिल सकता है बुनियादी ढांचे का दर्जा, उड़ानों को मिलेगी गति

नए हवाई मार्गों और निवेश पर रहेगा जोर

10 नए हवाईअड्डों और विमान निर्माण पर रहेगा सरकार का दांव

राहुल संपाल

देश के आसमान में उड़ानों की रफ्तार बढ़ाने के लिए आगामी आम बजट में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। पिछला साल इस क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, जहां तकनीकी खामियों और परिचालन संबंधी संकटों ने यात्रियों को परेशान किया। अब सरकार का पूरा ध्यान इन बाधाओं को दूर कर घरेलू विमानन बाजार को नई ऊंचाई देने पर है। माना जा रहा है कि इस बार बजट में न केवल आवंटन बढ़ेगा, बल्कि इस पूरे क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने की पुरानी मांग भी पूरी हो सकती है। इससे विमानन कंपनियों को बैंकों से आसान और सस्ता कर्ज मिल सकेगा।

400 हवाई अड्डों का खाका : केंद्र देश में हवाईअड्डों का जाल बिछाने की तैयारी में है। मौजूदा 164 हवाईअड्डों की संख्या को साल 2047 तक 400 तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसी दिशा में बजट में 10 नए हवाईअड्डों की घोषणा संभव है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी संकेत दिए हैं कि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर भीड़ कम करने के लिए उनके आसपास के 150 किमी के दायरे में छोटे हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे।

आत्मनिर्भरता
देश में ही बनेंगे यात्री विमान

बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वदेशी विमान निर्माण और शोध पर केंद्रित रह सकता है। सरकार चाहती है कि भारत केवल विमानों का खरीदार न बनकर उनके निर्माण और मरम्मत का बड़ा केंद्र बने। इसके लिए विमानों के रखरखाव और कलपुर्जों की रिपेयरिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। इससे विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश के लिए आकर्षित होंगी और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

किराए में मिल सकती है राहत : पिछले बजट में की गई करीब 10% की कटौती की भरपाई इस बार जरूरी है। यदि सरकार विमान ईंधन पर कर घटाती है और आयात होने वाले कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट देती है, तो विमानन कंपनियों की लागत घटेगी। इसका सीधा लाभ यात्रियों को सस्ते टिकट के रूप में मिल सकेगा।

- **सुरक्षा व निगरानी पर जोर :** हवाईअड्डों पर बढ़ती भीड़ और हालिया तकनीकी संकटों को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और सुरक्षा ब्यूरो के बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS LINE DELHI 31 JANUARY 2026

Flamingo Aerospace to buy six 68-seater aircraft from UAC

Our Bureau
Hyderabad

REGIONAL AVIATION. Founder and CEO of Flamingo Aerospace Subhakar Pappula on board UAC's IL-114-300 on static display at Wings India 2026 in Hyderabad SIDDHANT THAKUR

Flamingo Aerospace and United Aircraft Corporation (UAC) signed a purchase agreement for six 68-seater IL-114-300 regional aircraft at the ongoing India Wings 2026 here.

The partnership will eventually lead to the manufacture of the aircraft in India, thereby boosting the local supply chain and employment across the aviation sector.

As part of the agreement, UAC has offered Flamingo Aerospace a cooperation framework, including a detailed roadmap for developing aviation capabilities in India. The pact enables Flamingo Aerospace to undertake, in a phased manner, industrial activities such as aircraft assembly; customisation; maintenance, repair and overhaul(MRO) services; and preparation for manufacturing and infrastructure development.

"UAC stands as our strategic cornerstone partner in this mission, delivering cutting-edge aircraft, proprietary technologies, and localised manufacturing expertise to the Indian market," Subhakar Pappula, Founder and CEO, Flamingo Aerospace, said in a release.

Vadim Badekha, CEO, UAC, said: "The Indian air travel market is growing at the fastest rate in the world. Passenger numbers are growing annually by up to 11 per cent... This creates the preconditions for the commercial success of our regional aircraft in the local market."

EXPANSION PLAN

"While the signed framework agreement covers the delivery of six aircraft starting in 2028, we plan to expand our cooperation with Flamingo Aerospace to include new mutually beneficial collaborations in the future," he added.

The IL-114-300 is designed for short- to medium-haul operations, according to a release.

Heritage Aviation to buy Airbus H130 helicopter

Our Bureau
Hyderabad

Heritage Aviation has signed a purchase agreement for one Airbus H130 helicopter at the Wings India 2026 to expand its heli-pilgrimage and regional connectivity operations under the UDAN scheme.

"The helicopter industry in India is witnessing strong tailwinds due to the government's favourable policies and the strong demand environment. The new H130 will be used to expand our regional connectivity footprint in other areas, including north-east India, which largely remains virgin territory for private helicopter operations," Rohit Mathur, Founder and CEO, Heritage Aviation, said in a release on Friday. The helicopter is scheduled for delivery in September this year.

The chopper can accommodate a pilot and up to seven passengers, and is suited for operations in environmentally sensitive regions, the release added.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate
DESHBANDHU DELHI 1 FEBRUARY 2026

एयरबस को एच175 हेलीकॉप्टर के लिए मिला ऑर्डर

हैदराबाद। फ्रांस की कंपनी एयरबस कॉर्पोरेट हेलीकॉप्टर्स को एक निजी भारतीय ग्राहक से तीन हेलीकॉप्टरों के लिए ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने शनिवार को बताया कि उसे भारत से एच175 हेलीकॉप्टर के लिए पहला ऑर्डर मिला है। साथ ही दो ओसीएच160 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर मिले हैं। उक्त ऑपरेटर के बेड़े में एसीएच160 हेलीकॉप्टर के पहले से शामिल हैं। एच175 दो इंजन वाला सुपर-मीडियम हेलीकॉप्टर है जिसमें कुल 16 सीटें होंगी। इसकी डिलिवरी इसी साल होने की संभावना है। दो एसीएच160 हेलीकॉप्टरों को ग्राहक विशेष जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाएगा और उनकी डिलिवरी अगले साल होगी। यहां बेगमपेट हवाई अड्डे पर चल रहे विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम के दौरान इस ऑर्डर पर मुहर लगी। भारत और दक्षिण एशिया में एयरबस हेलीकॉप्टर के प्रमुख सन्नी गुगलानी ने कहा कि ये ऑर्डर देश में बढ़ते नागरिक हेलीकॉप्टरों के बाजार को रेखांकित करते हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

HARI BHUMI | DELHI | 1 FEBRUARY 2026

भारत में वायुमार्गीय यात्रा अप्रत्याशित रूप में असुरक्षित हुई है, इसमें संदेह नहीं है। प्रतिवर्ष कोई न कोई विमान दुर्घटना हो रही है, जो मानव को आधुनिकता तथा विज्ञान के अभिशाप से निरंतर परिचित करा रही है। बढ़ती आबादी, मध्यम वर्ग का विस्तार, व्यापार और पर्यटन में वृद्धि तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग ने हवाई यात्रा को अब केवल लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बना दिया है। वहीं, देखने में आता है कि राजनीतिक दबाव या समय की कमी के कारण विमान चालक प्रतिकूल मौसम में भी उड़ान भरने का जोखिम उठाते हैं, जबकि मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में राजनीतिक दबाव की तुलना में उड्डयन मानकों का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित होना अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। कह सकते हैं कि एविएशन सेक्टर में एक तरफ विकास की अपार संभावनाएं हैं तो दूसरी तरफ चुनौतियां भी मौजूद हैं। इसके लिए सरकार को इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी के साथ-साथ सिस्टम और सुरक्षा को भी मजबूत बनाना होगा, ताकि विमान हादसों पर यथासंभव रोक लगाई जा सके। दीर्घकालिक नीति, स्थिर निवेश, कौशल विकास, तकनीकी नवाचार और पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर ही इस क्षेत्र को वास्तव में सशक्त बनाया जा सकता है। इसी का विश्लेषण करता *आजकल* का यह खास अंक...

चुनौतियों से घिरीं वायुमार्गीय यात्राएं

विश्लेषण

विकेश कुमार बडोला
वरिष्ठ पत्रकार

हाल ही में हुई विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार की असामयिक मृत्यु ने देश में वीआईपी वायु यात्रा और वायु मार्गों के सुरक्षा प्रबंधन पर गंभीर प्रश्न खडे कर दिए हैं। भारत जैसे विशाल तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में राजनीतिक गतिविधियों और शासन के सुचारू संचालन के लिए आज विमान यात्रा एक आवश्यकता बन चुकी है, किंतु आवश्यकता के बढ़ने पर भी अधि संख्या में होने वाली विमान यात्राओं की शत-प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी है।

विमानों के माध्यम से वायुमार्गीय यात्रा अप्रत्याशित रूप में असुरक्षित हुई है, इसमें संदेह नहीं है। प्रतिवर्ष कोई न कोई विमान दुर्घटना हो ही रही है, जो मानव को आधुनिकता तथा विज्ञान के अभिशाप से निरंतर परिचित करा रही है। सीडीएस विपिन रावत का हेलिकॉप्टर, गुजरात में बोइंग विमान और अब महाराष्ट्र में अजित पवार का निजी विमान, सभी भयंकर रूप में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। उप-मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में असामयिक मृत्यु ने देश में वीआईपी वायु यात्रा और वायु मार्गों के सुरक्षा प्रबंधन पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। भारत जैसे विशाल तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में राजनीतिक गतिविधियों और शासन के सुचारू संचालन के लिए आज विमान यात्रा एक आवश्यकता बन चुकी है, किंतु आवश्यकता के बढ़ने पर भी अधि संख्या में होने वाली विमान यात्राओं की शत-प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी है।

हवाई पट्टियों का समुचित प्रबंधन

नवीन विमान दुर्घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत क्षति नहीं है, बल्कि इसने हमारे देश के विमानन सुरक्षा नवाचार तथा विशेष रूप में लघु नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हवाई पट्टियों के समुचित प्रबंधन पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। अजित पवार की मृत्यु ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वायुमार्गीय वीआईपी आवागमन की समयावधि में सुरक्षा के उच्चतम मानकों में थोड़ी सी भी चूक प्राणघाती सिद्ध हो सकती है। अभी भारत में कई ऐसी हवाई पट्टियां है जो जनपदीय प्रशासन के अधीन हैं, जहां नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निर्दिष्ट मानकों का पूर्ण पालन प्रायः चुनौतीपूर्ण होता है।

इस स्थिति में हवाई पट्टियों का समुचित संचालन अत्यावश्यक हो जाता है, और ऐसा होने पर ही वायुमार्ग का आवागमन सुरक्षा की परिधि में हो सकता है। विमान दुर्घटनाओं की त्रासदी के आलोक में, वीआईपी आवागमन को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक कार्य करने होंगे। इसके लिए सर्वप्रथम विमानन के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण आवश्यक है।

नेविगेशन की सुविधाएं नगण्य

देश में अधिसंख्य अस्थायी अथवा लघु आकार की हवाई पट्टियों पर रात्रि में विमान को उतारने की सुविधाएं व प्रबंधकीय व्यवस्थाएं अपर्याप्त हैं। प्रतिकूल वातावरण में नेविगेशन की सुविधाएं नगण्य हैं। जो सुविधाएं हैं, वे भी पुरानी हैं। इस दिशा में जो भी सुधार किए जाने हैं, वे तत्काल प्रभाव से युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए। इसके अंतर्गत सभी सक्रिय हवाई पट्टियों पर सटीक दृष्टिकोण पथसंकेतक लगाये जाएं। आधुनिक प्रकाश प्रणाली स्थापित की जाएं। रनवे की सतह और उसकी लंबाई का नियमित रूप में सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य हो। मौसम संबंधी पूर्वानुमान प्रणाली को दुर्घटनाओं की चुनौतियों के अनुसार सुदृढ़ किया जाना चाहिए। पहाड़ी या तटीय क्षेत्रों में, जहां मौसम क्षण-प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, वहां के लिए विशिष्ट पूर्वानुमान प्रणालियां सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित हों। उड़ानों के लिए केवल सामान्य मौसमीय जानकारी पर निर्भर रहने की तुलना मे, हवाई पट्टियों पर प्रतिक्षण की मौसमीय जानकारी देने वाले स्वचालित मौसम सूचना प्रणालियां स्थापित की जाएं। विमान चालकों को उड़ान भरने से ठीक पहले मौसम की उपयुक्त जानकारी सुनिश्चित की जाए।

उड्डयन मानकों का पालन

प्रायः देखने में आता है कि राजनीतिक दबाव या समय की कमी के कारण विमान चालक प्रतिकूल मौसम में भी उड़ान भरने का जोखिम उठाते हैं। जबकि मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में राजनीतिक दबाव की तुलना में उड्डयन मानकों का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित होना अधिक महत्वपूर्ण होगा। वीआईपी आवागमन का अंतिम निर्णय विमान चालक के स्तर पर होना चाहिए। वहीं निश्चित करें कि उड़ान भरी जानी है अथवा स्थगित करनी है। यदि विमान चालक मौसम या तकनीकी कारणों से उड़ान भरने से मना करता है, तो बिना किसी प्रशासनिक दबाव के उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके लिए सुरक्षा संबंधी अतिरिक्त समय-निर्धारण की कार्यसंस्कृति विकसित की जाए, जिसमें निर्धारण हेतु निर्णायक की भूमिका में विमान चालक ही हो। उड्डयन संबंधी जो भी मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित है, उसका हर परिस्थिति में कठोरतापूर्वक पालन हो। वैसे तो नागरिक उड्डयन महानिदेशक के पास वीआईपी आवागमन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश होते हैं, किंतु धरातल पर इनका पालन नहीं होता। देखा गया है कि राजनीतिक मनमर्जी ऐसे दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने देती। इस स्थिति पर उड्डयन संबंधी नियमों का कठोर नियंत्रण सुनिश्चित होना चाहिए।

ईंधन गुणवत्ता की सघन जांच

उड़ान से पूर्व विमानों की तकनीकी उपयुक्तता का प्रमाणपत्र तथा ईंधन की गुणवत्ता की द्विस्तरीय सघन जांच होनी चाहिए। विमान को भूमि पर उतारने तथा उड़ान की समयावधि मे विमान स्थल के कर्मचारियों और अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता अत्यंत अनिवार्य हो। विमान चालकों का प्रशिक्षण यदि गुणवत्तापूर्ण होगा तथा यदि उनके अधि कार्यघंटों को ध्यान में रख समुचित विश्राम देने का प्रबंधन नियमित होगा, तो भी दुर्घटनाओं की संभावनायें कम होंगी।

चालकों को हो विशेष अनुभव

देखा जाता है कि प्रायः एक ही चालक दल निरंतर कई यात्राओं में उड़ान व्यस्त होता है। यह स्थिति तत्काल प्रभाव से बदली जानी चाहिए। वीआईपी उड़ानों के लिए चालकों का विशेष अनुभव भी निर्धारित होना चाहिए। उन्नत संचार तकनीकों की भी वायुमार्गीय विमान यात्रा को सुरक्षित करने में व्यापक भूमिका हो सकती है।

इसके साथ ही, ध्यान रहे कि जिनके पास इनके संचालन का कार्यदायित्व हो, वे कार्य के प्रति निष्ठापूर्वक होकर समर्पित रहें।

संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी कम नहीं

दृष्टिकोण

विवेक शुक्ला
वरिष्ठ पत्रकार

भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। पिछले कुछ सालों में हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ी है, लेकिन विमानों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस साल एविएशन सेक्टर का भविष्य मिश्रित दिखाई देता है। एक तरफ विकास की संभावनाएं हैं, दूसरी तरफ चुनौतियां - जैसे विमान और पायलटों की कमी तथा वित्तीय नुकसान। सबसे पहले, विमानों की कमी की वजह समझते हैं। भारत में एयरलाइंस जैसे इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट तेजी से फैल रही हैं। विमान बनाने वाली कंपनियां जैसे बोइंग और एयरबस समय पर विमान नहीं दे पा रही हैं। सप्लाई चेन की समस्या, कच्चे माल की कमी और मजदूरों की कमी से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। जानकारों का मानना है, 2026 में घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक में सिर्फ 0-3% की बढ़ोतरी हो सकती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) की रिपोर्ट कहती है कि 2026 में हवाई यात्री ट्रैफिक में 4.9% की बढ़ोतरी होगी। भारत इसमें बड़ा योगदान देगा, क्योंकि यहां अर्थव्यवस्था मजबूत है और मध्यम वर्ग बढ़ रहा है। 2026 में एविएशन सेक्टर कैसा रहेगा? सकारात्मक पक्ष से शुरू करें। बोइंग ने घोषणा की है कि 2026 में भारतीय एयरलाइंस को 25 नए विमान दिए जाएंगे। यह क्षमता बढ़ाएगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कुल मिलाकर, भारत का फ्लीट 2026 में 100 से ज्यादा विमानों से बढ़ सकता है। एयरबस का अनुमान है कि 2035 तक भारत का कमर्शियल फ्लीट तीन गुना होकर 2250 विमानों तक पहुंच जाएगा। अभी यह 850 के आसपास है। यूनियन बजट में एविएशन पर फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, एयरपोर्ट क्षमता बढ़ाना और सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। विंग्स इंडिया 2026 जैसे इवेंट में नए सौदे और निवेश की बात हो रही है। बोइंग का कहना है कि 2044 तक भारत और दक्षिण एशिया को 3300 नए विमानों की जरूरत होगी, जिसमें 90% सिंगल-आइसल जेट होंगे। इससे रोजगार बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विमानों की कमी से एयरलाइंस ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। जानकारी के अनुसार, 2026 में वैश्विक स्तर पर 120 बिलियन डॉलर के नए विमान डिलीवर होंगे। भारत में पायलटों की कमी एक बड़ी समस्या है। बिजनेस एविएशन में पायलट शॉर्टेज और मेंटेनेंस की दिक्कतें हैं। 2035 तक 35,000 पायलटों की जरूरत होगी, अभी सिर्फ 12,000 हैं। टेक्निकल स्टाफ भी तीन गुना बढ़ाना पड़ेगा। अब बात सुधार की। एविएशन सेक्टर में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर और निवेश करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कहा गया है कि एविएशन, पोर्ट्स और शिपिंग में मजबूत ग्रोथ होगी, और जीडीपी ग्रोथ 7% तक पहुंच सकती है। 10 सालों में 200 एयरपोर्ट हो सकते हैं, अभी 150 हैं। मेक इन इंडिया के तहत विमान पार्ट्स बनाने वाली फैक्टरियां लगाएं। बोइंग और एयरबस से ज्यादा पार्टनरशिप करें। पायलट ट्रेनिंग के लिए नए संस्थान खोलें। मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स की लोकल सप्लाई चेन बनाएं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे एआई से उड़ान शेड्यूल ऑप्टिमाइज करें और साइबर सिक्योरिटी मजबूत करें। एयरलाइंस को फाइनेंशियल सपोर्ट दें, जैसे टैक्स छूट। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) पर फोकस करें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। 2025 में हुई दुर्घटनाओं से सीखें और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं। कुल मिलाकर, अगर ये सुधार किए गए तो 2027 में ट्रैफिक 6-8% बढ़ सकता है। इस बाबत ईमानदारी से प्रयास किए जाने जरूरी हैं। बेशक, 2026 में भारत का एविएशन सेक्टर चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन विकास की राह पर है। विमानों की कमी से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। अधिकतर एयरलाइंसों का अपने मुसाफिरों को लेकर रवैया कोई बहुत सही तरह का नहीं रहता। राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही अराजकता फैली रहती है। मुसाफिरों को यहां से वहां धक्के खाने पड़ते हैं। अगर सरकार, एयरलाइंस और मैन्युफैक्चरर्स मिलकर काम करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन सकता है। यह न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि लाखों लोगों को रोजगार देगा। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

> **बोइंग का कहना है कि 2044 तक भारत और दक्षिण एशिया को 3300 नए विमानों की जरूरत होगी, जिसमें 90% सिंगल-आइजल जेट होंगे। इससे रोजगार बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विमानों की कमी से एयरलाइंस ग्रोथ नहीं कर पा रही है।**

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

HARI BHUMI DELHI 1 FEBRUARY 2026

कनेक्टिविटी के साथ-साथ सिस्टम पर भी ध्यान दे सरकार

व्यवस्था
रवि शंकर
स्वतंत्र पत्रकार

भारतीय एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्रैश, साइबर अटैक, तकनीकी खराबियों और उड़ानों में अव्यवस्था ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। बजट 2026 से उम्मीद है कि सरकार कनेक्टिविटी के साथ-साथ सिस्टम और सुरक्षा को भी मजबूत करेगी।

भारतीय एविएशन के लिए बीता हुआ साल बेहद मुश्किल साल रहा। एयर इंडिया का एक जानलेवा हादसा, एयरलाइंस और एयरपोर्ट सिस्टम पर साइबर अटैक, लगातार टेक्निकल खराबियां और दिसंबर में इंडिगो की बड़ी गड़बड़ी ने दिखा दिया कि सिस्टम कितना नाजुक हो गया है। इंडियन एविएशन सेक्टर आज जिस स्थिति में खड़ा है, उसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की आसमान में उड़ान भरने की महत्वाकांक्षा और उसकी जमीनी हकीकत के बीच बेहद गहरा अंतर है। बीते दशक में भारत ने एविएशन के बुनियादी ढांचे, एयरपोर्ट्स, क्षेत्रीय संपर्क और यात्रियों की संख्या के लिहाज से अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की है, लेकिन एयरलाइंस के ऑपरेशन्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कम्पेटिटिव एनवायरमेंट के मोर्चे पर तीव्र संकट से गुजर रहे है। सवाल अहम है कि क्या भारत की एविएशन इंडस्ट्री जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उसे सुरक्षित रखने वाले सिस्टम भी मजबूत हो रहे हैं? पहले चर्चा सिर्फ विस्तार (एक्सपेंशन) की होती थी, अब बात दबाव और जोखिम की होने लगी है।

आज की स्थिति में इंडिगो जैसी विमान कंपनियों की मोनोपोली जितनी यात्रियों के लिए हानिकारक है, उतनी ही उद्योग के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए भी है।

यह विरोधाभास जितना चौंकाने वाला है, उतना ही चिंताजनक भी। भारत में एविएशन सेक्टर में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यह विकास टिकाऊ तभी होगा, जब मार्केट स्ट्रक्चर हेल्दी हो, नीतियां संतुलित हों और रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग हो। आज की स्थिति में इंडिगो जैसी कंपनियों की मोनोपोली जितनी यात्रियों के लिए हानिकारक है, उतनी ही उद्योग के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए भी। भारतीय एविएशन सेक्टर को गौर से देखें तो यह दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट है, जो अभी मुख्यतः इंडिगो और एयर इंडिया पर ही टिका है। भारी संख्या में फ्लाइट पैसेंजर होने के बावजूद दूसरी कोई एयरलाइंस इस इंडस्ट्री में प्रभावी नहीं है। एविएशन एक्सपर्ट के मुताबिक, यह कोई सामान्य समस्या नहीं है, बल्कि खराब पॉलिसी का नतीजा है। पिछले 20 सालों में जब भी जेट एयरवेज या किंगफिशर जैसी बड़ी एयरलाइंस डूबीं, तो उस समय भी सरकार की ओर से इन कंपनियों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर सरकार समय से कदम उठाती तो संभवतः आज हजारों नौकरियां सुरक्षित और हमारी हवाई क्षमता बेहतर होती। सरकार एविएशन सेक्टर में किसी भी तरह के नए निवेश को आकर्षित करने में विफल रही है। आज, सरकार की बहुप्रचारित 'उड़ान' योजना का हश्र देखिए। दावा था 2,500 रुपये में हवाई यात्रा का, लेकिन दिसंबर 2025 में सरकार खुद 1500 किमी से कम की उड़ानों के लिए 18,000 रुपये तक की कैपिंग (सीमा) लगा रही है। एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और अधिक एयरलाइंस की सख्त जरूरत है। वर्तमान में, भारतीय घरेलू विमानन बाजार पर मुख्य रूप से दो बड़े समूहों का वर्चस्व है, जिससे प्रतिस्पर्धा का संतुलन बिगड़ गया है। बाजार का लगभग 90 फीसदी हिस्सा केवल इन दो समूहों (इंडिगो और टाटा) के नियंत्रण में है। भारत में और एयरलाइंस की सख्त आवश्यकता है। नई एयरलाइंस न केवल किराया कम करने में मदद करेंगी, बल्कि परिचालन संकट के समय बाजार को स्थिरता भी प्रदान करेंगी। भारत का एविएशन उद्योग सालाना 10 से 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, यह दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ है। उस हिसाब से नए निवेश को आकर्षित करना चाहिए। मौजूदा हालात से बचने के लिए सरकार को अपना लागत ढांचा तर्कसंगत बनाना चाहिए। अभी बेइंतहां टैक्स है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स यात्रियों से तरह-तरह के शुल्क ले रहे हैं। जीएसटी आदि के नाम पर भी तरह तरह के टैक्स हैं। इन सारी वजहों से इस सेक्टर पर नए निवेश नहीं आ पा रहे हैं।

दूसरी सलाह है, बाजार हिस्सेदारी की सीमा तय की जानी चाहिए और 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। भारत यदि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनना चाहता है तो उसे नीतियों को बिस्तार से परे जाकर गहराई में सुधारना होगा। सबसे पहला उपाय होना चाहिए, एटीएफ को जीएसटी में लाना, दूसरा डीजीसीए को अधिक स्वायत्त, सशक्त और उत्तरदायी संस्था बनाया जाए, तीसरा यात्रियों को यूरोपीय मॉडल की तरह मुआवजे का कानूनी अधिकार मिले और चौथा नए खिलाड़ियों के प्रवेश को सरल बनाया जाना चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे। भारत का एविएशन सेक्टर आज आईसीयू में है। हमने 'प्रतिस्पर्धा' को मारकर 'एकाधिकार' को चुना है। 2009 के 'राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति' ने जिस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना देखा था, उसे आज 'सेल्फी पॉइंट्स' और महंगे एयरपोर्ट बर्गर में बदल दिया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

HARI BHUMI | DELHI | 1 FEBRUARY 2026

एविएशन सेक्टर : थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है

विस्तार
सुशील देव
स्वतंत्र पत्रकार

निश्चित तौर पर भारत का एविएशन सेक्टर यानी उड्डयन क्षेत्र बीते एक दशक में तेजी से विकसित हुआ है। बढ़ती आबादी, मध्यम वर्ग का विस्तार, व्यापार और पर्यटन में वृद्धि तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग ने हवाई यात्रा को अब केवल लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बना दिया है। आज हवाई सफर समाज के हर वर्ग की पहुंच में आता दिखाई दे रहा है।

यह बदलाव भारत की बदलती आर्थिक और सामाजिक तस्वीर को भी दर्शाता है। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने देशभर में हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर विशेष जोर दिया है। पटना, दतिया, सतना, अमरावती, तूतीकोरिन, पूर्णिया, नवी मुंबई और गुवाहाटी जैसे शहरों में नए एयरपोर्ट और आधुनिक टर्मिनल सुविधाओं का विकास किया गया है। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत हुई है और बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी ने इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ाया है। इसके बावजूद यह कहना जल्दबाजी होगी कि हम पूरी तरह संतुष्ट स्थिति में पहुंच चुके हैं। इस क्षेत्र में अभी कई बुनियादी जरूरतें और कमियां मौजूद हैं। सीनियर एविएशन कंसल्टेंट जी. एस. बाबा के अनुसार, हम प्रगति के रास्ते पर जरूर हैं और संभावनाएं भी बहुत हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले विमानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ पायलटों के प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और रखरखाव ढांचे को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की दिशा में तेज प्रगति भी समय की मांग है। विमानों की उपलब्धता के संदर्भ में भी बड़ा अंतर दिखाई देता है। वर्तमान जरूरतों और भविष्य की मांग को देखते हुए बेड़े के विस्तार की आवश्यकता है। ऐसे में 'मेक इन इंडिया' के तहत विमान निर्माण और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास सकारात्मक संकेत देते हैं। पायलट प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल विकास के लिए समर्पित समझौते (एमओयू) और प्रशिक्षण ढांचे का विस्तार भी उत्साहजनक कदम है। साथ ही भारत में एमआरओ (मेंटिनेंस, रिपेयर और ओवरहाल) सुविधाओं का विकास इस क्षेत्र को

दीर्घकालिक नीति, स्थिर निवेश, कौशल विकास, तकनीकी नवाचार और पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर ही इस क्षेत्र को वास्तव में सशक्त बनाया जा सकता है।

आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेक्टर की रीढ़ है। यदि हम घरेलू यातायात को बेहतर ढंग से विकसित और व्यवस्थित कर लें, तो आत्मनिर्भर एविएशन प्रणाली बनाना कठिन नहीं होगा।सरकार द्वारा छोटे एयरपोर्ट के विकास और छोटे विमानों के संचालन को बढ़ावा देना एक प्रभावी रणनीति साबित हो सकती है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना 'उड़ान' के माध्यम से टू-टियर और थ्री-टियर शहरों को जोड़ने का प्रयास सराहनीय है। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और पर्यावरण-अनुकूल नीतियों पर काम भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप है।हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कई एयरलाइंस आर्थिक दबाव का सामना कर चुकी हैं। ईंधन की ऊंची कीमतें, जटिल टैक्स ढांचा, सीमित एयरपोर्ट स्लॉट, परिचालन लागत और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी विकास की गति को प्रभावित करती है। छोटे हवाई अड्डों की व्यावसायिक व्यवहार्यता भी एक गंभीर प्रश्न है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाता है, पर यात्री संख्या और उड़ानों की निरंतरता सुनिश्चित करना चुनौती बना रहता है। सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन भी इस क्षेत्र की अनिवार्य जरूरतें हैं। बढ़ते हवाई यातायात के साथ सुरक्षा मानकों को और सख्त करना होगा। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, विमान रखरखाव और तकनीकी निगरानी को विश्वस्तरीय बनाना आवश्यक है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम करने और हरित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यह भी जरूरी है कि एविएशन सेक्टर केवल महानगरों तक सीमित न रहे। उत्तर-पूर्व, पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में हवाई संपर्क जीवनरेखा का काम कर सकता है। मेडिकल इमरजेंसी, आपदा प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए नीतियों में लाभ के साथ सामाजिक उपयोगिता को भी बराबर महत्व मिलना चाहिए। भारत जैसा विशाल और उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश अभी एविएशन संभावनाओं का केवल एक छोटा हिस्सा ही उपयोग कर पाया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत का एविएशन सेक्टर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन यात्रा अभी अधूरी है। दीर्घकालिक नीति, स्थिर निवेश, कौशल विकास, तकनीकी नवाचार और पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर ही इस क्षेत्र को वास्तव में सशक्त बनाया जा सकता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

HARI BHUMI | DELHI | 1 FEBRUARY 2026

हवाई आधारभूत संरचना में मजबूती लाना जरूरी

मुद्दा
वरिष्ठ पत्रकार
योगेश कुमार सोनी

बीती 28 जनवरी को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। इस घटना से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार विजिबिलिटी कम होने की वजह से बारामती में रनवे नहीं दिखा और लैंडिंग की कोशिश नाकाम हो गई थी, इसलिए यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि विमान दुर्घटना की जांच को लेकर भारत में इसके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है? और यह सच संपूर्ण रूप से बाहर आ पाता है या नहीं कि दुर्घटना किस वजह से हुई? कमर्शियल से लेकर प्राइवेट प्लेन तक दुर्घटनाओं की चपेट में आ रहे हैं। जबकि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में प्लेन का सफर सबसे ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। चूंकि यदि छोटी सी भी घटना या प्लेन में कोई कमी हो जाए तो निश्चित तौर पर मौत तय है और इसलिए प्लेन की पूरी तरह से जांच होनी अनिवार्य होती है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना यह है कि जिस स्तर पर भारत की जनसंख्या बढ़ी और हर तरह के विमान में बढ़ोतरी हुई, उस स्तर पर सिस्टम अपडेट व अपग्रेड नहीं हुआ। आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच साल में भारत में कुल 53 हवाई हादसे हुए हैं। इन हादसों में कुल 320 से ज्यादा लोगों की जान गई है। जबकि करीब 180 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

वहीं, साल 1947 से लेकर अब तक हुए हादसों में 2,000 से अधिक लोगों की जान गई है। भारत में कुल 487 हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां हैं जिनमें से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 137 का प्रबंधन करता है इनमें 34 अंतरराष्ट्रीय और कई घरेलू हवाई अड्डे शामिल हैं और भारत में लगभग 148 परिचालन हवाई अड्डे हैं, जो यात्रियों को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। यह कमर्शियल व प्राइवेट दोनों के लिए है। देश में लगभग हर वर्ष एक बड़ा विमान हादसा हो रहा है। इससे तंत्र प्रणाली को सबक लेना चाहिए, चूंकि केवल बजट पारित करने के अलावा हाई टेक सिस्टम के साथ अपडेट होने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार खासतौर पर टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान मौसम का असर सबसे घातक साबित होता है। मौसम सीधे तौर पर विमान की विजिबिलिटी बैलेंस, इंजन कैपेसिटी और पायलट के निर्णय को प्रभावित करता है। खराब मौसम में एक छोटी-सी चूक भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी भी फ्लाइट के कुल समय का केवल 5 से 6 प्रतिशत हिस्सा टेकऑफ और लैंडिंग में लगता है लेकिन 70 प्रतिशत से ज्यादा हवाई हादसे इसी चरण में होते हैं और इसके लिए हम किसी भी रूप में अपडेट नहीं हो पाते। यही कारण है कि हम विमान के हादसे की सही से जांच नहीं कर पाते। इसकी वजह से अधिकतर मामलों में सच सामने आ ही नहीं पाता। हमारा इंफ्रा उतना मजबूत नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मुख्य काम हवाई अड्डों की योजना, सुरक्षा, विमान नियम बनाना और हवाई यातायात सेवाओं की देखरेख करना है, लेकिन इतने बड़े मंत्रालय के पास अधिकतर अपने कार्य से संबंधित उत्तर नहीं होता तो इसमें आम आदमी को सही उत्तर कहां से मिलेगा। यदि भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े तो उसके लिए हमारे पास अधिकतर रूट पर बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है और स्थिति तो यह भी है कि बड़े-बड़े एयरपोर्ट के पास तक कॉलोनियां बसी हुई हैं। हम हादसों से पहले कभी जागते नहीं और कुछ दिन मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर फिर से पुराने ढर्रे पर चल पड़ते हैं। बहरहाल, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इस तरह के हादसे हों, लेकिन यदि किसी घटना की आशंका जिस वजह से ज्यादा हो, उस पर गंभीरता दिखाना सरकार का कर्तव्य माना जाता है। उड्डयन तंत्र प्रणाली को लेकर भी अब सजग होना अनिवार्य है। हमारे देश में हर रोज लगभग 6 लाख लोग हवाई सफर करते हैं। हवा में यात्रा करना भरोसा होता है सिस्टम पर, चूंकि एक विमान में 600 तक लोगों के बैठने की क्षमता होती है और उसके संचालित करने के लिए टीम होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते दशक भर में हमारे देश में सड़कों पर बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ है और हम इसी तरह की उम्मीद हवाई यात्रा की तंत्र प्रणाली के लिए करते हैं, चूंकि अब हवाई सफर करने वालों की संख्या हर रोज बढ़ रही है।

विशेषज्ञों का मानना यह है कि जिस स्तर पर भारत की जनसंख्या बढ़ी और हर तरह के विमान में बढ़ोतरी हुई, उस स्तर पर सिस्टम अपडेट व अपग्रेड नहीं हुआ।

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

Corporate Communications Directorate

HINDUSTAN TIMES | DELHI | 1 FEBRUARY 2026

Scrutiny mounts on AAIB as 2023 crash report stuck

Neha LM Tripathi

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The civil aviation ministry's 2024-25 annual report states that of 104 accidents, investigations into 91 had been completed by December 31, 2024, with 88 final reports made public. As per International Civil Aviation Organization (ICAO) norms, investigations such as these require a final report within a year of the incident.

HT looked back at Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) final reports and found that among the delayed reports is that of a September 2023 runway accident involving VSR Aviation, the company from which Maharashtra deputy chief minister Ajit Pawar chartered the Learjet 45 that crashed on Wednesday, killing him and four others.

The delay has raised questions about AAIB's capacity, but more critically, experts said the missing findings could have determined if VSR Aviation required stricter oversight long before the Baramati crash.

"It is still unclear whether the 2023 incident was purely weather-related or linked to technical issues. Had the final findings been released, it would have clarified whether corrective action was required," said an aviation professional, requesting anonymity.

The September 2023 accident saw a VSR Learjet 45, registration VT-DBL, break into two pieces during a heavy rain landing at Mumbai airport. All six occupants survived with injuries. AAIB issued a preliminary report one month after the crash, stating that flight recorder data had been downloaded and records relating to

continued on →8

Among the delayed AAIB reports is that of a 2023 runway accident involving VSR Aviation, the firm from which Ajit Pawar chartered the Learjet 45 that crashed on Wednesday. RAJU SHINDE/HT

Hindustan Times

(FROM PAGE 1)

utilise duty-free access to Europe, describing the proposed India-EU pact as the "Mother of All Deals".

The budget will align with the "Viksit Bharat" and "Atmanirbhar Bharat" (Self-reliant India) goals. Priorities include strategic defence, energy security, semiconductors, rare earth minerals and digital sovereignty, the officials said.

AAIB REPORT

maintenance, crew, radar, air traffic control communications and the enhanced ground proximity warning system had been sent for analysis.

However, 16 months later, the final findings have not been released.

The ministry report also shows that of 121 serious incidents, 108 investigations were completed with 107 final reports released, leaving at least one report delayed and 13 pending probe. The September 2023 incident, with no fatalities, was classified as an "accident", while the Baramati crash, and incidents that involve the potential of mass casualties, are likely to be considered as a "serious incident".

Investigation backlogs and resource constraints

JS Rawat, former joint director general of the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), said every accident occurs due to a unique set of factors as he stressed on the need for stricter timelines. "The sole purpose of an investigation report is to understand what went wrong and how such incidents can be avoided in the future," he said. "The weather conditions in Mumbai and Baramati were different. That said, as per norms, the report should have been released within a year. Since there were no fatalities in the Mumbai aircraft skid, the authorities should have completed the investigation in accordance with the rules."

Rawat emphasised: "It is high time that a reasonable timeline should be defined for completing an investigation".

One former bureaucrat familiar with the agency said AAIB is beset with staff shortages, functions "barely with 8-10 people". "With the aviation sector expanding rapidly, the AAIB needs adequate staffing. Its role is vital, yet it has not received the attention it deserves," he added.

Unregulated boom?

Pilots and former regulators pointed to deeper problems now exposed by the Baramati crash: oversight of non-scheduled operator (NSOP) ecosystem.

A former pilot, familiar with VSR Aviation's practices, said operators like it "wait for the aircraft to break and then fix it, with very poor oversight in CAMO [Continuing Airworthiness Management Organisation], maintenance and quality. Pilots are manipulated to fly poorly maintained aircraft".

VSR did not respond to requests for a comment.

Another pilot said under-reporting of flight hours is common among many NSOPs to delay expensive maintenance.

A sector expert said this was an open secret. "It is widely known that operators like them under-report aircraft and engine hours to prolong maintenance. The OEM 'on-condition' rules are ignored until components fail. Engines fly with high vibration and low temperature margins; I have seen fan blades chipped beyond limits," said Mark D Martin of Martin Consulting.

Martin added that several chartered jets operate with critical equipment inoperative. "Unlike airlines, NSOPs must pay upfront cash for parts costing $30,000 to $150,000. The mantra is not maintenance but 'paisa vasool'," he said.

The former bureaucrat quoted above said VSR is alleged to maintain multiple log books shown to DGCA inspectors. "By under-logging hours, it is obvious that the maintenance cycle is also delayed," he said. "This is a clever way to deal with the annual surveillance and spot checks by the DGCA. However, there is a need for the regulator to seek flight plans from the Airports Authority of India to cross-check the operators' claims. This will ensure that NSOPs do not take safety for granted."

A former DGCA official cautioned against painting all NSOPs with the same brush. "Big corporate operators — such as Reliance or Bajaj — do not compromise on safety. The problem lies with jet operators and their attitude," one official said.

But a second official agreed: "The recent crash has highlighted the need for a change of the system. Neither should pilots agree to fly such planes, nor should operators stretch them to do so. But if the majority of NSOPs are frequent in such violations then an accident or incident will remain unavoidable."

SUNETRA PAWAR

plane crash has halted the merger talks," he told reporters earlier in the day.

Ajit Pawar and four others were killed in a plane crash in Baramati on Wednesday morning, ending an era in state politics.

Earlier in the day, Sunetra Pawar was also elected leader of the NCP's legislative party at a meeting of its lawmakers at the Vidhan Bhavan. Hours later, she was sworn in as deputy chief minister at Lok Bhavan in a ceremony attended by Fadnavis, deputy chief minister Eknath Shinde and all senior leaders and legislators of the NCP.

Sunetra Pawar will also contest the by-election from the Baramati constituency, said an NCP leader on condition of anonymity. According to the rules, she can continue as a Rajya Sabha member until she is elected to another House, such as the Maharashtra assembly. The bypoll will be conducted within six months.

Maharashtra governor Devvrat administered the oath to Sunetra Pawar on Saturday evening. The ceremony concluded amid slogans of "Ajit dada amar rahe" (Long live Ajit dada) and "Vahini saheb age badho, hum tumhare saath hain" (Sister-in-law, move forward, we are with you). Her younger son, Jay, was present at the event.

"Although his [Ajit] untimely passing has left a mountain of sorrow upon my heart, the values he taught, dedication to duty, the strength to struggle and an unwavering commitment to the people, are my true source of strength. I will continue to work with complete honesty and dedication to realise his dream of a just, egalitarian, and developed Maharashtra," Sunetra Pawar said on X.

No member of the Sharad Pawar family attended the ceremony. In an apparent ...

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

INDIAN EXPRESS DELHI 1 FEBRUARY 2026

HC pulls up DGCA over 'indefinite' pilot rest rules changes

Sohini Ghosh
New Delhi, January 31

THE DELHI High Court has sought a response from the DGCA and questioned its rationale to disallow clubbing of pilots' leave with weekly rest, even as the regulator clarified that weekly rest under the Flight Duty Time Limitations (FDTL) "has never been withdrawn, is non-negotiable, and no exemption has been granted to any of the airlines".

A division bench of Chief Justice DK Upadhyaya and Justice Tejas Karia on Friday issued notice to DGCA and IndiGo, and granted them two weeks to file their reply to a PIL that objected to a December 5, 2025, instruction by the regulator where it had declared an indefinite withdrawal of the clause of 'no leave shall be substituted for weekly rest'.

Chief Justice Upadhyaya inquired orally from the DGCA, "What is the rationale for this? And it applies to all airlines...Why have you withdrawn it?"

DGCA's counsel Anjana Gosain submitted that during an audit in November 2025, it was reported by airlines that leaves were being clubbed with weekly rest periods.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

JANSATTA DELHI 1 FEBRUARY 2026

देश में चार्टर्ड और निजी विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं बढ़ी हैं। बारामती में अजित पवार की हवाई हादसे में मौत से कई गंभीर सवाल उठे हैं। व्यावसायिक एअरलाइंस की तुलना में अनिर्धारित समय-सारिणी वाली उड़ानों (एनएसओपी) के हादसे तकनीकी खामियों के साथ ही देश के विमानन सुरक्षा ढांचे पर भी सवाल खड़े करते हैं। पिछले साल हुए एअर इंडिया के विमान हादसे को कुछ ही समय बीता था कि जनवरी 2026 की हाल की घटना ने इस बहस को और तेज कर दिया है। इन हादसों के पीछे नियामक ढांचे की कमजोरी ही मुख्य वजह मानी जा रही है। देश को भविष्य में बारामती या केदारनाथ जैसी त्रासदियों को रोकना है, तो डीजीसीए को कागजी कार्रवाई से निकलकर जमीनी स्तर जांच और पायलट प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। विमानन सुरक्षा को खर्च के बजाय अनिवार्यता के रूप में देखना ही एकमात्र समाधान है। सरोकार की पड़ताल...

हवा में मौत

अहमदाबाद हादसे के बाद बारामती दुर्घटना ने झकझोरा नियामक एजंसी की कमजोरियां फिर सामने आईं

जनसत्ता सरोकार

पिछले कुछ वर्षों में चार्टर्ड विमानों और हेलिकाप्टरों के दुर्घटनाग्रस्त होने की दर में वृद्धि देखी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) की रपटों के अनुसार, भारत में छोटे विमानों की सुरक्षा पर जोर बड़े व्यावसायिक विमानों की तुलना में काफी कम है। साल 2025 में दुनिया भर में लगभग 50 बड़े विमान हादसे हुए, जिनमें एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा चार्टर्ड और निजी उड़ानों का था। भारत में पांच वर्षों में चार्टर्ड विमानों और हेलिकाप्टरों के 15 से अधिक गंभीर हादसे दर्ज किए गए हैं। हाल का हादसा 28 जनवरी 2026 का है, जिसमें महाराष्ट्र के बारामती में एक लेयरजेट45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें अजित पवार चालक दल सहित सभी पांच लोगों की मृत्यु हो गई। यह विमान एक निजी चार्टर कंपनी वीएसआर वेंचर्स का था।

भारत में पिछले दो दशकों में लगभग 95 विमान हादसे हुए हैं। यह संख्या एशिया में विमान दुर्घटनाओं के मामले में इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान रखती है। जहां तक भारत बनाम अमेरिका और यूरोप का सवाल है, अक्सर माना जाता है कि विकसित देशों में हादसे कम होते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ अलग कहानी कहते हैं। हालांकि, वहां निजी विमानन का दायरा भारत से बहुत बड़ा है। अमेरिका में सबसे बड़ा निजी और चार्टर विमान बेड़ा है।

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) के अनुसार अमेरिका में हर साल लगभग 1,200 से 1,500 छोटे विमानों के हादसे होते हैं। यहां प्रति 1,00,000 उड़ान घंटों पर दुर्घटना दर व्यावसायिक उड़ानों की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक है। यूरोप में प्रति वर्ष औसतन 150 से 200 लोग छोटे विमानों के हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। ब्रिटेन में यूरोप के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक (लगभग 110) विमान हादसे दर्ज किए गए हैं।

चार्टर्ड और निजी विमानों के असुरक्षित होने के पीछे कई संरचनात्मक और परिचालन संबंधी कारण हैं। पायलटों के अनुभव और प्रशिक्षण में बड़ा अंतर है। व्यावसायिक एअरलाइंस के पायलटों के लिए 1,500 उड़ान घंटों का अनुभव अनिवार्य होता है, जबकि निजी पायलट लाइसेंस (पीपीएल) केवल 40 घंटों में मिल सकता है। चार्टर्ड उड़ानों में अक्सर पायलट विजुअल फ्लाइट रूल्स (वीएआर) पर निर्भर रहते हैं, जिससे अचानक मौसम बिगड़ने पर वे नियंत्रण खो देते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी भी बड़ा कारण है। चार्टर्ड विमान अक्सर छोटे और दूरदराज के हवाई अड्डों (जैसे बारामती या पहाड़ी क्षेत्र) पर उतरते हैं। वहां विमान उतारने की प्रणाली की कमी होती है। कोई पूर्णकालिक वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) टावर नहीं होता है।

मौसम के प्रति संवेदनशीलता भी छोटे विमानों (जैसे लेयरजेट या सेस्ना) को मुश्किलों में डालती है क्योंकि ये कम वजन के होते हैं। ये तेज हवाओं और अचानक हुई बारिश को बोइंग या एअरबस विमानों की तरह नहीं झेल सकते। भारत में टेबलटाप रनवे और पहाड़ी इलाकों में अचानक छाने वाला कोहरा इनके लिए काल बन जाता है। इनका रखरखाव और नियामक निरीक्षण भी कमजोर होता है। व्यावसायिक एअरलाइंस का डीजीसीए द्वारा बेहद कड़ा परीक्षण किया जाता है। इसके विपरीत, निजी और अनिर्धारित विमान संचालकों के पास अक्सर संसाधनों की कमी होती है। कई बार कतरब्योंत के चक्कर में पुर्जों के रखरखाव में लापरवाही बरती जाती है। फिर पायलटों की थकान और दबाव भी चार्टर्ड उड़ानों में अक्सर दिक्कत पैदा करता है। पायलटों पर वीआइपी यात्रियों को उनके गंतव्य तक समय पर पहुंचाने का मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। यह दबाव उन्हें खराब मौसम में भी विमान उतारने के लिए मजबूर कर देता है।

भारत में पिछले दो दशकों में लगभग 95 विमान हादसे हुए हैं, जो इसे एशिया में विमान दुर्घटनाओं के मामले में इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पर रखते हैं। जहां तक भारत बनाम अमेरिका और यूरोप का सवाल है, अक्सर माना जाता है कि विकसित देशों में हादसे कम होते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ अलग कहानी कहते हैं।

आखिर छोटे विमानों के हादसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देश में चार्टर्ड विमानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केवल नियम बनाना काफी नहीं है, बल्कि उनका सख्ती से पालन भी जरूरी है। संसदीय समितियों ने हाल ही में डीजीसीए में कर्मचारियों की कमी दूर करने और निजी संचालकों के औचक परीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। छोटे विमानों की सुरक्षा के लिए भविष्य में आंकड़ों पर आधारित जोखिम आकलन और छोटे हवाई अड्डों पर नौवहन संबंधी सहायता का आधुनिकीकरण भी अनिवार्य हो गया है। जब तक निजी संचालक सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर नहीं रखेंगे, तब तक आसमान में जोखिम बना रहेगा। हाल में सरकार ने संसद में बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में करीब 50 फीसद पद खाली हैं। वहीं, एअरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया में लगभग 38 फीसद और एअर ट्रैफिक कंट्रोल में करीब 23 फीसद पद खाली हैं। इन खाली पदों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया धीमी होने के कारण विमानन सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन पदों को भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे और सुरक्षा मानकों को मजबूत किया जाएगा।

सरकार के मुताबिक डीजीसीए में कुल 1,630 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 805 पद खाली हैं। यानी लगभग आधे पदों पर ही कर्मचारी तैनात हैं। एअरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया में कुल 25,730 पदों में से सिर्फ 16,011 पर ही नियुक्ति हुई है, जबकि 9,719 पद अभी भी खाली हैं। एअर ट्रैफिक कंट्रोल में भी स्थिति बेहतर नहीं है। 5,537 पदों में से 1,274 पद अभी खाली हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में खाली पद होने से विमानन सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।

संसदीय स्थायी समिति रपट (साल 2022-23 और 2024) : परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर बनी स्थायी समिति की 334वीं रपट (साल 2022) और 358वीं रपट (2024) में विमानन सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर कड़े सवाल उठाए गए थे। इसी में डीजीसीए के पास तब 19% से 25% तकनीकी पदों के खाली होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था।

संसदीय समिति रपट संख्या 361 (अगस्त 2024)
इस रपट में विशेष रूप से हेलिकाप्टर और चार्टर्ड विमान संचालन की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें छोटे हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे की कमी को हादसों की बड़ी वजह बताया गया।

डीजीसीए वार्षिक सुरक्षा रपट (साल 2023 और 2024): वार्षिक आंकड़ों (2023-24) में यह स्पष्ट किया गया कि व्यावसायिक एअरलाइंस की तुलना में चार्टर्ड संचालकों में दुर्घटनाओं की दर स्थिर नहीं है। इसमें मानवीय त्रुटि का 70 फीसद योगदान है।

एएआइबी इन्वेंट्री (साल 2020-2025): विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की पांच वर्षों की घटनाओं के अध्ययन (जैसे साल 2021 में हुए केदारनाथ हेलिकाप्टर हादसे और साल 2023 के छोटे चार्टर हादसों की अंतिम रपट) से पायलट की थकान और दबाव में विमान उतारने के तथ्य लिए गए हैं।

सुरक्षा सुधार हेतु ठोस सुझाव

संसदीय समितियों की सिफारिशों और सुरक्षा विशेषज्ञों के मत के आधार पर निम्न सुधार अनिवार्य हैं।

1. स्वतंत्र नियामक संस्था

समिति ने बार-बार सुझाव दिया है कि एएआइबी को मंत्रालय और डीजीसीए के प्रशासनिक नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। जब जांच करने वाली संस्था स्वतंत्र होगी, तभी संचालकों की लापरवाही को बिना किसी दबाव के उजागर किया जा सकेगा।

2. पायलट निगरानी का आधुनिकीकरण

चार्टर्ड पायलटों के लिए एफओक्यूए (उड़ान संचालन गुणवत्ता आश्वासन) आंकड़ों का नियमित विश्लेषण अनिवार्य किया जाना चाहिए। वर्तमान में यह केवल बड़ी एअरलाइंस के लिए सख्ती से लागू है। इससे यह पता चलेगा कि क्या पायलट उड़ान के दौरान खतरनाक पैंतरे अपना रहा है।

3. छोटे हवाई अड्डों का परीक्षण

भारत के दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के हवाई अड्डों की सुरक्षा जांच होना चाहिए। संसदीय समिति (साल 2024) ने सिफारिश की है कि चार्टर्ड विमानों द्वारा उपयोग किए जाने वाली 50 वैकल्पिक विमान पट्टियों पर रात में उतरने और स्वचालित मौसम केंद्र सुविधा उपलब्ध कर कराई जाए।

देखा जाए तो भारतीय आसमान में चार्टर्ड विमानों का बढ़ता उपयोग देश की आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर यह प्रगति जोखिम भरी है। भारत, अमेरिका और यूरोप के तुलनात्मक अध्ययन और संसदीय समितियों के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दुर्घटनाएं केवल तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि नियामक चूक का परिणाम भी हैं। अमेरिका और यूरोप में छोटे विमान हादसों की संख्या अधिक है। दरअसल वहां हजारों निजी विमान रोजाना उड़ते हैं, वहीं भारत में कम संख्या होने के बावजूद मृत्यु दर का उच्च होना चिंताजनक है। अमेरिका में हादसों की संख्या अधिक है प्रति वर्ष 1,200 है, लेकिन वहां विमानों की संख्या भी भारत से 500 गुना अधिक है। भारत में मृत्यु दर प्रति दुर्घटना तुलनात्मक रूप से अधिक है।

संसदीय समितियों की हाल के वर्षों में पेश रपट में कई चिंताजनक पहलू

देश में चार्टर्ड और निजी विमानन सुरक्षा को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और संसदीय स्थायी समितियों की रपट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि प्रणालीगत भी है।

संसदीय समिति की चिंताएं : काफी पद खाली हैं और संरचना का संकट है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने रपट में भारतीय विमानन क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैः-

डीजीसीए में कर्मियों की भारी कमी : समिति ने पाया कि डीजीसीए में तकनीकी पदों पर भारी कमी है। पर्याप्त वायु सुरक्षा निरीक्षक न होने के कारण छोटे चार्टर संचालकों पर निगरानी नहीं रह जाती है।

अनिर्धारित संचालकों का परमिट (एनएसओपी) का लचीलापन : समिति ने यह भी इंगित किया कि निर्धारित एअरलाइंस (जैसे इंडिगो, एअर इंडिया) के मुकाबले चार्टर्ड संचालकों के लिए नियम थोड़े लचीले हैं, जिसका फायदा उठाकर कई कंपनियां सुरक्षा नियमों की अनदेखी करती हैं।

छोटे हवाई अड्डों पर निवेश का अभाव : 'उड़ान' योजना में कई नए हवाई अड्डे खुले हैं, लेकिन वहां रात में विमान उतारने की सुविधाएं और उन्नत मौसम रिपोर्टिंग प्रणाली का अभाव है।

नियंत्रित भूभाग में उड़ान (सीएफआइटी) : छोटे विमानों और हेलिकाप्टरों के दुर्घटनाग्रस्त होने का सबसे बड़ा कारण सीएफआइटी है। इसका मतलब है कि विमान पूरी तरह नियंत्रण में था, लेकिन पायलट ने खराब दृश्यता या नौवहन गलती के कारण टकरा दिया। भारत में चार्टर्ड विमान हादसों में से लगभग 40% से 50% मामले खराब मौसम और पायलट के विशेष दिशानिर्देशों की अनदेखी के कारण होते हैं।

पायलट दक्षता जांच (पीपीसी) : डीजीसीए के परीक्षण में पाया गया कि कई छोटे चार्टर संचालक अपने पायलटों की नियमित सिम्युलेटर रिफ्रेशर ट्रेनिंग नहीं करवाते।

सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) का अभाव

परीक्षण रपटों से पता चला है कि कई चार्टर कंपनियां केवल कागजों पर सुरक्षा नियमों का पालन दिखाती हैं। वास्तविक जमीनी संचालन में जल्दी उड़ान भरने के चक्कर में विमान की जांच ठीक से नहीं होती है।

चार्टर्ड विमानों का तकनीकी ढांचा

व्यावसायिक व चार्टर्ड विमानों के बीच सुरक्षा का मुख्य अंतर अतिरिक्त प्रणाली में होता है : **एकल इंजन बनाम दो इंजन :** कई निजी विमान एकल इंजन वाले होते हैं। **ब्लैक बाक्स (एफडीआर/सीवीआर):** चार्टर्ड विमानों में कई बार पुराने माडल के डेटा रिकार्डर होते हैं या डेटा विश्लेषण पुख्ता नहीं होता।

महाराष्ट्र में पहले भी हुए हैं हादसे

बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में अजित पवार की मौत से महाराष्ट्र स्तब्ध रह गया, जिससे हाल के वर्षों में हवाई और हेलिकाप्टर दुर्घटनाओं से जुड़े राज्य के नेताओं की चिंताजनक सूची में उनका नाम भी जुड़ गया।

25 मई, 2017 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लातूर के पास एक हेलिकाप्टर दुर्घटना में बाल-बाल बच गए थे। सरकारी स्वामित्व वाला सिकोरस्की हेलिकाप्टर नीलांगा के हेलीपैड से उड़ान भरने ही वाला था कि तेज हवाओं के कारण पायलट को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। फडणवीस और पांच अन्य लोग बाल-बाल बच गए।

22 मई, 2017 को, मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक अन्य हेलीकाप्टर में माओवादी प्रभावित गढ़चिरोली में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उन्हें उड़ान रद्द करके सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी।

2 अक्तूबर, 2024 को सुरक्षा संबंधी चिंताएं एक बार फिर सामने आईं, जब राज्यसभा सांसद सुनील तटकरे को ले जा रहा एक हेलिकाप्टर पुणे के पास उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हेलिकाप्टर, जिसमें तटकरे एक दिन पहले यात्रा कर चुके थे, उन्हें वापस लेने के लिए लौट रहा था। इसमें दो पायलट और एक रखरखाव इंजीनियर की मौत हो गई।

4 मई, 2024 को रायगढ़ जिले के महाड में शिवसेना यूबीटी नेता सुषमा अंधारे को लेने आया एक बेल 407 हेलिकाप्टर अस्थायी हेलीपैड पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

2 जनवरी, 2025 को राकांपा (शरद) के प्रमुख शरद पवार और राज्य पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल को ले जाने वाला हेलिकाप्टर कोंकण क्षेत्र के चिपलुन में बने एक अस्थायी हेलीपैड से दो बार उड़ान भरने में विफल रहा। दोनों बार हेलिकाप्टर को तत्काल उतारना पड़ा। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

LOKH SATYA DELHI 1 FEBRUARY 2026

एयरबस को भारत के पहले एच175 हेलीकॉप्टर के लिए मिला ऑर्डर

नई दिल्ली/हैदराबाद, लोकसत्य। फ्रांस की कंपनी एयरबस कॉर्पोरेट हेलीकॉप्टर्स को एक निजी भारतीय ग्राहक से तीन हेलीकॉप्टर के ऑर्डर मिले हैं। इसमें एक एच175 हेलीकॉप्टर और दो एसीएच160 हेलीकॉप्टर शामिल है। हालांकि, इसकी कीमत की जानकारी कंपनी ने साझा नहीं किया है। एयरबस कॉर्पोरेट हेलीकॉप्टर्स ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने एक निजी भारतीय ग्राहक के साथ दो एसीएच 160 हेलीकॉप्टर और एक एच175 हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर साइन किया है। यह ऑपरेटर पहले से ही एसीएच 160 का ग्राहक है, जो भारत का पहला एच175 हेलीकॉप्टर ग्राहक बनेगा। कंपनी ने बताया कि भारतीय सिविल मार्केट में सुपर-मीडियम ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर की एंट्री के साथ एच175 हेलीकॉप्टर 16-सीट कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। इसकी डिलीवरी 2026 में होने वाली है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

MILLANIUM POST | DELHI | 1 FEBRUARY 2026

Airbus secures historic order for India's first H175 and two ACH160s

Airbus Corporate Helicopters has signed an order for two ACH160 helicopters and one H175 with a private Indian customer. The operator is an existing ACH160 customer and will become India's first H175 customer. Marking the introduction of the super-medium twin-engine helicopter into the Indian civil market, the H175 helicopter will come in a 16-seat configuration with delivery scheduled for 2026. The two ACH160 helicopters will be exclusively configured as per customer's requirements and will be delivered in 2027. The ACH160 represents an impressive combination of power and elegance. Backed by cutting-edge technology, the ACH160 allows business leaders to bridge time and reach, enabling impactful decisions where it matters, when it matters.

अहमदाबाद बोइंग हादसा जांच की सूई पायलट की ओर

■ जानबूझकर इंजन बंद किए जाने की दिशा में फोकस हो रही जांच

लंदन, 31 जनवरी (विशेष) : पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद में हुए बोइंग ड्रीमलाइनर हादसे के संबंध में जांच की दिशा पायलट पर फोकस हो गई है।

इस बात के संकेत बताए जा रहे हैं कि पायलट ने जानबूझ कर विमान के इंजन बंद कर दिए थे।

ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विशेषज्ञों ने हादसे के पीछे किसी तकनीकी कारण से स्पष्ट इनकार कर चुके हैं। उन्हें इस मामले में तोड़फोड़ के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जांच पायलट द्वारा जानबूझ कर उठाए गए एक्शन की ओर बढ़ रही है। इस संबंध में अभी तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।

नाम न बताने की शर्त पर जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पायलट की गतिविधि की ओर जांच मजबूती से मुड़ गई है। दूसरी ओर अधिकारी और पायलट के परिजन पूर्व में भी चर्चा में आई ऐसी कथित रिपोर्ट्स का पुरजोर विरोध कर चुके हैं, जिनमें पायलट की गलती बताने की कोशिश की गई थी।

56 वर्षीय सुमित सभ्रवाल उस उड़ान के कप्तान थे। उन्हें 15600 घंटे उड़ान का अनुभव था। उनके साथी पायलट क्लाइव कुंदर थे, जिन्हें 3403 घंटे(शेष पृष्ठ 11 कालम 3 पर)

ईंधन स्विच ऑफ हुए

एएआईबी की ओर से पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती जांच में पाया गया था कि उड़ान भरने के कुछ सैकेंड बाद ही विमान को ईंधन सप्लाई करने वाले दोनों स्विच ऑफ हो गए थे। इससे दोनों इंजन बंद हो गए और विमान ने अपनी ऊंचाई खो दी। रिपोर्ट में कॉकपिट में दोनों पायलट्स की बात का एक हिस्सा भी जारी किया गया था, इसमें एक पायलट को दूसरे से यह कहते हुए सुना कि आपने स्विच क्यों बंद किए, इसके जवाब में दूसरा कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ यह लगाया जा रहा है कि विमान के साथ कोई तकनीकी समस्या नहीं थी। वहीं पायलट यूनियन और परिजनों का कहना है कि विमान निर्माता बोइंग को बचाने के लिए पायलटों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

TIMES OF INDIA | DELHI | 1 FEBRUARY 2026

Charter operator VSR was benched by EU regulator before Pawar plane crash

Suspension Order Also Marked To DGCA

Manju.V@timesofindia.com

Mumbai: European aviation regulator EASA (European Union Aviation Safety Agency) suspended its third country operator authorisation of Indian charter operator VSR Ventures more than a year ago, citing a "Level 1" safety finding after the company failed to provide documents and information repeatedly sought in the Sept 2023 Learjet 45 accident in Mumbai.

EASA had also marked the suspension order to DGCA. Last week, another Learjet operated by VSR crashed near Baramati, killing Ajit Pawar and four others. A "Level 1" safety finding is EASA's most serious category of non-compliance, issued when a safety risk cannot be ruled out or when an operator fails to cooperate with regulatory oversight.

Wreckage of the chartered plane carrying Ajit Pawar and 4 others

Under EASA's safety oversight framework, a TCO authorisation is mandatory for any non-EU aircraft operator to land or overfly European airspace. The authorisation implies that the operator meets international safety standards. VSR did not comment on a query sent by TOI.

▶ Access denied, P 13

VSR denied EU regulator access to safety records

▶ **Continued from P 1**

The operator did not grant access to EASA to the requested documents and information. In the absence of safety-relevant information and data provided by the operator, the agency could not determine, as part of its monitoring obligations, the operator's continued compliance with the applicable requirement of TCO, said the suspension order, accessed by **TOI**.

The operator did not provide information about the accident involving Learjet-45 in Mumbai, it said. "EASA was interested in safety recommendations potentially addressed to the air carrier and outcome of internal investigations, notably with regard to any measure(s) taken in addressing potential contributing factors," it added.

The suspension order listed five dates in Oct and Nov 2024 when EASA sent reminders to VSR seeking information about the accident and received no response.

"VSR was given an opportunity to take adequate measures on Level 1 finding and propose acceptable corrective action plans, together with a root cause analysis and proposed implementation timelines," the order said, citing reason for TCO suspension.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

TIMES OF INDIA | AHMEDABAD | 31 JANUARY 2026

Kuwait-Delhi flight makes emergency landing at SVPI

Was Diverted To Ahmedabad Following Bomb Threat

Times News Network

Ahmedabad: An IndiGo flight operating from Kuwait to Delhi made an emergency landing at the Sardar Vallabhbhai Patel International (SVPI) Airport in Ahmedabad on Friday morning after a written bomb threat was detected onboard.

The incident prompted the pilot to activate emergency security protocols. Some 180 passengers, including six crew members, were aboard the flight.

The aircraft, IndiGo flight 6E1232, was diverted as a precaution after a handwritten chit claiming a bomb was aboard the flight was found near a passenger seat during the flight, as learned from sources. The pilot immediately alerted air traffic control (ATC), following which the aircraft landed at SVPI Airport around 6.40am.

After landing, the aircraft was taken to an isolation bay where bomb disposal squads, fire brigade teams and medical staff were already deployed.

All passengers were safely deboarded and moved to a secure holding area, while the aircraft was subjected to thorough security checks. No injuries or panic were reported.

"Soon after the landing, teams from the bomb detection and disposal squad (BDDS), Central Industrial Security Force (CISF), airport security and local police rushed to the spot. Officials confirmed that a comprehensive anti-sabotage and security check of the aircraft was underway. Passenger baggage and cargo were also thoroughly screened as part of the laid-down procedures," a source told TOI.

Handwriting samples of passengers were also collected and taken for examination, sources said.

Sources confirmed that the flight later departed for the Indira Gandhi International (IGI) Airport in Delhi around 4.20pm.

In a statement, an IndiGo spokesperson said, "IndiGo flight 6E1232 operating from Kuwait to Delhi on Jan 30, 2026 was diverted to Ahmedabad after a security threat was noticed onboard. The authorities concerned were immediately informed, and all the mandated protocols were followed. The aircraft was cleared after all necessary checks and the flight departed shortly."

Airport sources said flight operations at Ahmedabad airport continued uninterrupted.

Security agencies launched an investigation to trace the source of and motive behind the threat.

Why indefinite relaxation on pilot rest norm, SC asks DGCA

Abhinav.Garg@timesofindia.com

New Delhi: Delhi high court on Friday questioned the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) over the "indefinite" relaxation granted to airlines on implementing the new regulations governing pilots' weekly rest and leave.

Hearing a PIL that raised the issue, a bench of Chief Justice D K Upadhyaya and Justice Tejas Karia sought an explanation as to why the aviation regulator deferred the implementation of the new flight-duty norms soon after introducing them. "What is the rationale for withdrawal of this? And this applies to all airlines," the bench asked the DGCA counsel. The HC issued notice, giving DGCA two weeks' time to respond.

The new regulations mandate that "no leave shall be substituted by weekly rest". On Dec 5, 2025, DGCA eased the Flight Duty Time Limitations to allow IndiGo to deploy more pilots on duty in order to reduce disruptions. The move came after IndiGo cancelled hundreds of flights nationwide in the first week of Dec after failing to prepare for the implementation of the new flight-duty norms for pilots.

TRIBUNE DELHI 1 FEBRUARY 2026

Airbus secures order for three civil helicopters at Wings India

TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, JANUARY 31
Airbus Corporate Helicopters in Wings India-2026 has secured an order for three civil helicopters from a private Indian customer, including two ACH160s and one H175, marking the first induction of the H175 into the country's civil helicopter market.

The operator, already an ACH160 customer, will become the country's first civil user of the super-medium, twin-engine H175 helicopter. The aircraft will be delivered in a 16-seat passenger configuration, with induction scheduled for 2026. The two additional ACH160 helicopters will be customised to the customer's specific requirements and are expected to be delivered in 2027.

Airbus said both helicopter types are well-suited for passenger operations, offering a mix of performance, range and cabin comfort.

Sunny Guglani, Head of Airbus Helicopters in India and South Asia, said the repeat purchase of the ACH160 and the first-ever H175 order from an Indian customer reflected the increasing maturity of the country's civil helicopter market. He said the helicopters were designed to meet evolving passenger transport needs while delivering strong performance and comfort.

The ACH160 is positioned as a premium corporate helicopter, combining advanced technology with a focus on reliability and design. Airbus said the model enabled business and private operators to maximise time efficiency, allowing rapid point-to-point connectivity while maintaining high safety and comfort standards. The H175, which sits in the super-medium category, strengthens Airbus Helicopters' civil lineup with its versatility and operational flexibility. The aircraft offers extended range and payload capability, making it suitable for passenger transport.